



दैनिक जागरण

www.dainikjagranmpcg.com



वर्ष 69 अंक 142 पृष्ठ 12
भोपाल, गुरुवार 19 फरवरी 2026
फाल्गुन शुक्ल पक्ष 02 विक्रम संवत् 2082
महानगर मूल्य 5 रुपए

4.38 लाख करोड़ का बजट: मप्र पहला राज्य जहां रोलिंग बजट के आधार पर विकास की अवधारणा

23882
लाइली बहना
40062
ग्रामीण विकास

किसान का 'सम्मान' बहना का भी बढ़ाया मान

विशेष संवाददाता, भोपाल। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मोहन सरकार का तीसरा बजट सदन में पेश किया। 4.38 लाख करोड़ के बजट में किसान के कल्याण और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। किसानों को 1 लाख सोलर पंप देने 3 हजार करोड़ तो लाइली बहना के लिए 23882 करोड़ का बजट तय किया गया है। जगदीश देवड़ा ने अपने डेढ़ घंटे के बजट भाषण के दौरान कहा, देश में मप्र ऐसा पहला राज्य है, जहां रोलिंग बजट के आधार पर विकास की अवधारणा तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वर्ष कृषि और किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे में बजट में कृषि विभाग के लिए 1 लाख 15 हजार 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कृषि की कई योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। देवड़ा ने कहा कि जब हम किसानों की आय को दोगुना करने की बात करते हैं, तो उन्हें जहां प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके लिए 21 लाख 42 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, तो दुग्ध उत्पादन की दिशा में भी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। गहन पशु विकास परियोजना के लिए 838 करोड़, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 250 करोड़ की राशि का बजट में प्रावधान किया गया है।



गरीब कल्याण के लिए 793 करोड़ रुपए

देवड़ा ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए 793 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा प्रारम्भ की जाएगी। बजट में मजरा टोला सड़क योजना के लिए 21 हजार 630

करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इससे 20,900 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। यदि कि सरकार अब छोटी आबादी वाले क्षेत्रों में भी सुगम सड़क मार्ग उपलब्ध कराएगी। सड़कों की मरम्मत के लिए भी 12,690 करोड़ का

प्रावधान किया गया है। क्षतिग्रस्त पुलों के नवनिर्माण के तहत 4,572 करोड़ की राशि बजट में स्वीकृत की गई है। सड़कों और पुलों के निर्माण, संधारण के लिए 12,690 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

गांवों में नवाचार के लिए 3736 करोड़

सरकार पंचायतों को तकनीकी तौर पर सक्षम बनाने के लिए बजट में बतौर अनुदान 3736 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं ग्रामीण विकास को लेकर भी कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 4062 करोड़ का वित्तीय प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना सुविधाएं, आजीविका और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभावों को कम करने के कार्य शामिल किए जाएंगे। इस योजना के तहत अब पाठों को 100 दिन की बजाए 125 का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गांवों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अगले वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय और 505 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।

बजट संबोधन के दौरान देवड़ा ने पूंजीगत व्यय पर जोर देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 80,266 करोड़ रुपए का पूंजीगत बजट रहने का अनुमान है। इसमें यदि अन्य माध्यमों से जुटाए गए संसाधनों को जोड़ दें, तो प्रभावी कैपेक्स 1.10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

3000 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने के लिए प्रावधान

412 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बड़ा प्रयास।

21630 मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क के लिए

श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़। ग्रामीण और शहरी सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़

23747 शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए

उद्यम क्रांति -युवाओं को लोन के लिए 16,451 करोड़। नारी कल्याण -1 लाख 27,555 करोड़

2149 स्वास्थ्य क्षेत्र-आयुष्मान और अन्य मदों के लिए

जनजातीय क्षेत्र के 11,277 गांवों के लिए 793 करोड़। जल जीवन मिशन -4,454 करोड़

3060 सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए (सोलर पंप के अतिरिक्त)

44605 केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए

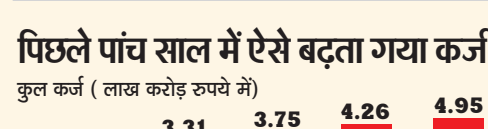
नोट : (राशि करोड़ रुपए में)

मध्यप्रदेश का बजट पिछले पांच सालों में लगातार बढ़ते ही चल रहा है। यह वृद्धि राज्य की आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, राजस्व संग्रह में सुधार और विकास परियोजनाओं में बढ़ते निवेश को दर्शाती है।

बीते पांच साल में लगातार बढ़ा बजट



पिछले पांच साल में ऐसे बढ़ता गया कर्ज



बीते पांच वर्ष में कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ा है। कुल कर्ज हर वर्ष नई ऊंचाई पर पहुंचता गया है।

सपनों को साकार करने वाला बजट

यह बजट समृद्ध मध्यप्रदेश, संपन्न मध्यप्रदेश, सुखद मध्यप्रदेश, सांस्कृतिक मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश की जनता पर किसी नए कद का बोझ नहीं डाला गया है। सुशासन और सुप्रबंधन के लिए निरंतर नवाचार और विकास के सभी पैमानों को पूरा करता यह बजट अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण के संकल्प में हमारी सरकार ने अब इंटरैक्टिव और इंफ्रास्ट्रक्चर के आई को भी शामिल किया है। यह बजट ज्ञानी के मार्गदर्शी सिद्धांत पर तैयार किया है।



जगदीश देवड़ा, मुख्यमंत्री

झूठे और खोखले वादों का बजट

मध्यप्रदेश सरकार का बजट झूठे आंकड़ों और खोखले वादों का बजट है। जनता के साथ छलावा है। यह जमीनी हकीकत से कटा हुआ है। बजट में रिकॉर्ड राजकोपीय घाटा, फिर भी योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है। वित्तमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि राजकोपीय घाटा 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा। जब सरकार के पास संसाधन ही नहीं हैं, तो योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? -उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

सपनों को साकार करने वाला बजट

यह बजट समृद्ध मध्यप्रदेश, संपन्न मध्यप्रदेश, सुखद मध्यप्रदेश, सांस्कृतिक मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश की जनता पर किसी नए कद का बोझ नहीं डाला गया है। सुशासन और सुप्रबंधन के लिए निरंतर नवाचार और विकास के सभी पैमानों को पूरा करता यह बजट अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण के संकल्प में हमारी सरकार ने अब इंटरैक्टिव और इंफ्रास्ट्रक्चर के आई को भी शामिल किया है। यह बजट ज्ञानी के मार्गदर्शी सिद्धांत पर तैयार किया है।

शहरी और ग्रामीण विकास

नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 के 50,566 करोड़ रुपए की तुलना में 2026-27 के लिए 61,665 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह 22 फीसदी की वृद्धि है, जो शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान है। इसके तहत हजारों करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित किए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा और बीमा

फसल बीमा के लिए 1,299 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 5,501 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए भी 5,501 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम किसान के तहत किसानों को 12,000 रुपए वार्षिक सहायता का उल्लेख है, जो पत्यक्ष आय समर्थन की नीति को दर्शाता है।

सस्ती बिजली और शून्य ब्याज ऋण

कृषि पंपों के लिए बिजली बिल राहत पर 20,485 करोड़ रुपए का प्रावधान दर्शाया गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान है। इसके तहत हजारों करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित किए जाएंगे।

उत्पत्तिकी और खाद्य प्रसंस्करण

उत्पत्तिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए 772 करोड़ का प्रावधान है। फल, सब्जी और मसाला उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। इससे फसल विविधीकरण का लाभ मिलेगा।

कृषि से जुड़े पशुपालन-मत्स्य-उद्यानिकी पर भी किया गया फोकस

25,000 करोड़ रुपए ऋण का लक्ष्य

कृषि के साथ-साथ उससे जुड़े क्षेत्रों उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन पर भी विशेष फोकस किया गया है। 'अन्नदाता' को बजट के प्रमुख स्तंभों में शामिल करते हुए सरकार ने आय के विविध स्रोत विकसित करने की रणनीति अपनाई है। इसी क्रम में इन क्षेत्रों के लिए 25,000 हजार करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में 2,365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुपालन के लिए 2,364 करोड़ का उल्लेख है। यह राशि डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य

सेवाओं, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और नस्ल सुधार पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को बड़े पैमाने पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। 2,364 करोड़ रुपए की ऋण सहायता का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

मत्स्य पालन और मछुआ कल्याण विभाग के लिए 413 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे तालाब विकास, मत्स्य बीज वितरण, कोल्ड चेन और विपणन सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

महिला कल्याण: 1,27,555 करोड़ रुपए का प्रावधान, लाइली बहना योजना की राशि बढ़ी

राज्य के बजट 2026-27 में महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट दस्तावेज में 'नारी शक्ति' को प्रमुख स्तंभों में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर महिला कल्याण से जुड़े प्रावधानों के लिए 1,27,555 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है।

सबसे बड़ा एलान लाइली बहना योजना को लेकर है। योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि 1,250 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। यह वृद्धि सीधे तौर पर करोड़ों महिलाओं के घरेलू बजट को सहारा देगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक निर्भरता कम होगी, बल्कि परिवार के खर्चों में उनकी भागीदारी और निर्णय क्षमता भी बढ़ेगी।

सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित



23882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है लाइली बहना के लिए, जबकि 1801 करोड़ रुपए का प्रावधान है लाइली लक्ष्मी योजना के तहत

कार्यरत महिलाओं के लिए सुविधाएं पिछले बजट की घोषणाओं के तहत वरिष्ठा दुर्गम डॉक्टर के कार्य प्रगति पर हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। यह पहल महिलाओं की श्रम भागीदारी दर बढ़ाने में मददगार हो सकती है।

अनुमान 25,967 करोड़ रुपए की तुलना में 2026-27 के लिए 32,730 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह 15 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे पोषण, आंगनवाड़ी सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा महिला सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी।

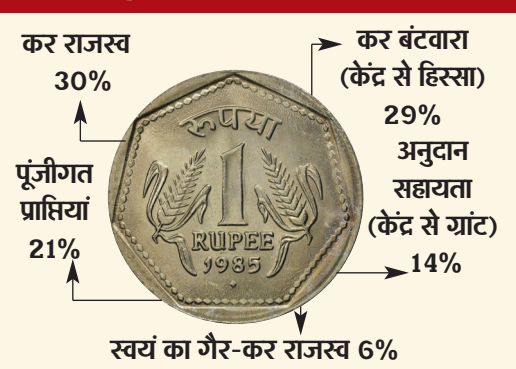
बजट पर खास पेज 2 और 8 पर

सामाजिक क्षेत्र के लिए 56478 करोड़ आवंटित, पिछले साल से 15% अधिक

शहरी और ग्रामीण विकास

नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 के 50,566 करोड़ रुपए की तुलना में 2026-27 के लिए 61,665 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह 22 फीसदी की वृद्धि है, जो शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान है। इसके तहत हजारों करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित किए जाएंगे।

कहां से आएगा रुपया



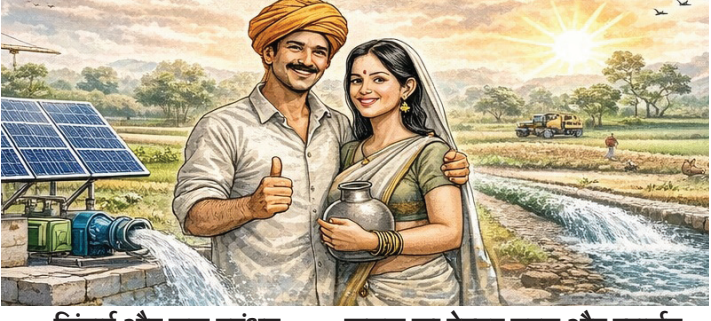
कहां जाएगा रुपया

संस्कृति एवं सामाजिक क्षेत्र	14%	स्वास्थ्य	13%	बुनियादी ढांचा	11%
शिक्षा	10%	कृषि	9%	ब्याज भुगतान	8%
सामान्य सेवाएं	9%	अन्य मदों में खर्च			
ऋण पुनर्भुगतान	8%	अन्य सेवाएं	4%		
पेंशन	7%	रोजगार क्षेत्र	1%		
सामाजिक क्षेत्र	5%	संस्कृति	0.5%		

'अन्नदाता': 'किसान कल्याण वर्ष' में कृषि निवेश बढ़ाने का संदेश, उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि पर फोकस

किसान कल्याण पर खर्च होंगे 1.15 लाख करोड़

कृषि को आर्थिक विकास की रीढ़ मानते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। बजट के स्तंभों में 'अन्नदाता' को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित करते हुए कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का संदेश दिया है। बजट दस्तावेज के अनुसार किसान कल्याण पर कुल 1,15,013 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि, मजबूत आदान व्यवस्था, बेहतर मूल्य और सुरक्षा तंत्र शामिल हैं। कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 88,910 करोड़ रुपए तथा किसानों के लिए कुल वित्तीय संसाधन 1.15 लाख करोड़ रुपए दर्शाए गए हैं, जो इसी व्यापक प्रावधान का हिस्सा है। किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख सोलर सिंचाई पंप लगाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। बजट में प्रधानमंत्री सूर्य कृषक मित्र योजना के अंतर्गत सीर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भी राशि का उल्लेख है। इससे डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटेगी और लागत में कमी आएगी।



सिंचाई और जल प्रबंधन

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश का प्रावधान है। भू-संरक्षण, लघु सिंचाई पंप और सिक्लर योजनाओं के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है।

फसल का बेहतर मूल्य और उपार्जन

उपज के बेहतर मूल्य के लिए व्यापक स्तर पर फसल उपार्जन और भावांतर योजनाओं को जारी रखा है। गेहूँ, धान, सोयाबीन और अन्य फसलों की खरीद के लिए बजट प्रावधान है। बोनस राशि और मंडी सुविधाओं के विस्तार से बाजार तक पहुंच आसान बनाने का प्रयास है।

फसल बीमा के लिए 1,299 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 5,501 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए भी 5,501 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम किसान के तहत किसानों को 12,000 रुपए वार्षिक सहायता का उल्लेख है, जो पत्यक्ष आय समर्थन की नीति को दर्शाता है। सस्ती बिजली और शून्य ब्याज ऋण: कृषि पंपों के लिए बिजली बिल राहत पर 20,485 करोड़ रुपए का प्रावधान दर्शाया गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान है। इसके तहत हजारों करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित किए जाएंगे। उत्पत्तिकी और खाद्य प्रसंस्करण: उत्पत्तिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए 772 करोड़ का प्रावधान है। फल, सब्जी और मसाला उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। इससे फसल विविधीकरण का लाभ मिलेगा।

कृषि के साथ-साथ उससे जुड़े क्षेत्रों उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन पर भी विशेष फोकस किया गया है। 'अन्नदाता' को बजट के प्रमुख स्तंभों में शामिल करते हुए सरकार ने आय के विविध स्रोत विकसित करने की रणनीति अपनाई है। इसी क्रम में इन क्षेत्रों के लिए 25,000 हजार करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में 2,365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुपालन के लिए 2,364 करोड़ का उल्लेख है। यह राशि डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य

विभागों का हाल: महिला बाल विकास को 32730 करोड़, आयुष को 1210 करोड़

विशेष संवाददाता, भोपाल। प्रदेश सरकार के बजट में सामाजिक क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। महिला और बाल विकास के अलावा शिक्षा, एससीएसटी व ओबीसी के साथ कृषि नगरीय और ग्रामीण विकास, संस्कृति संवर्धन और रोजगार पर भी फोकस किया गया है। बजट में सामाजिक क्षेत्र के महिला बाल विकास के बजट में वृद्धि की गई है। मंत्री निर्मला भूरिया के विभाग को 32,730 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में विभाग को 25,976 करोड़ का बजट दिया गया था।

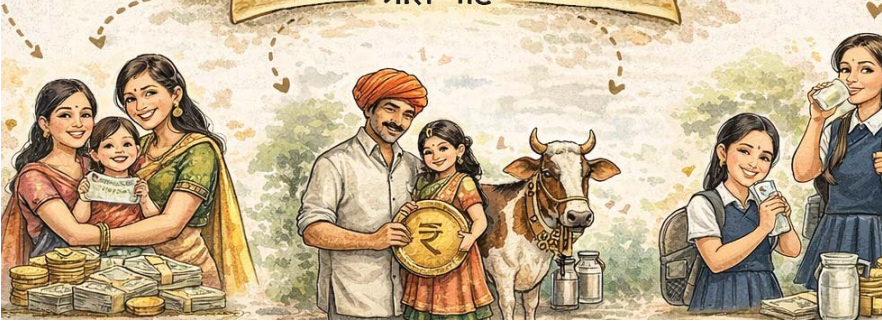
इसी तरह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट में भी इस बार वृद्धि हुई है। पिछले बजट में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस विभाग को 21.731 करोड़ की राशि मिली थी, जो इस बार 22.363 लाख हो गई है।

मंत्री इंद्र सिंह परमार के आयुष विभाग का बजट जहाँ 1,210 करोड़ रखा गया है, तो भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग को 175 करोड़ बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। इस तरह सामाजिक क्षेत्र में आने वाले इन विभागों में पिछले बजट की तुलना में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।



स्कूली और उच्च शिक्षा को 41 हजार करोड़

इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बार सरकार ने बजट में वृद्धि की है। यह 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के स्कूल शिक्षा विभाग को 36.730 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग को 4.247, मंत्री गौतम टेववाल के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को 2.932, मंत्री विश्वास सारंग के विभाग खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 715 करोड़, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को 734 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। मंत्री सारंग के विभाग सहकारिता को 1.679 करोड़ मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को 413 करोड़ दिए गए हैं।



नगरीय आवास को 21 हजार करोड़, पंचायत को 10 हजार करोड़

कैलाश विजयवर्गीय के विभाग नगरीय विकास एवं आवास को 21,665 करोड़, प्रहलाद पटेल के विभाग को 29,663 करोड़, उन्हीं के पंचायत विभाग को 10,440 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों का बजट पिछली बार की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ा है। गोविंद सिंह राजपूत के विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को 1,863 करोड़, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन सिंह के पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग को 2,365 करोड़, की राशि आवंटित की गई है। धर्मदेव भाव लोधी के पर्यटन विभाग को 566 करोड़,

संस्कृति विभाग को 1,365 करोड़, धर्मस्व और आनंद विभाग को 12 करोड़ की राशि दी है। इस तरह संस्कृति संवर्धन के क्षेत्र में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। सरकार ने रोजगार के क्षेत्र से जुड़े विभागों के बजट में 23 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसमें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को 3,814 करोड़, एमएसएमई को 2,144 करोड़, मंत्री दिलीप जायसवाल के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को 145 करोड़ की राशि देने की बात बजट में की गई है।

अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2591 करोड़ की राशि आवंटित

सरकार ने अपने बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग पर भी ध्यान दिया है। सदन में प्रस्तुत बजट में मंत्री विजय शाह के विभाग जनजातीय कार्यविभाग को 15,015 करोड़, मंत्री नागर सिंह चौहान के विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को 2,591 करोड़, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, घुमन्तु, अर्धघुमन्तु विभाग को 55 करोड़ का बजट दिया है। पिछली बार इस विभाग को 60 करोड़ का बजट दिया गया था। कृषि कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने कृषि के क्षेत्र में आने वाले विभागों पर भी विशेष ध्यान दिया है। मंत्री एदल सिंह कंधाना के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को 31,759 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।



कमलनाथ बोले- जनता से विश्वासघात वाला बजट

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता से विश्वासघात वाला बजट है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है, उसमें सिर्फ बाताओं के बतारो बनाए गए हैं। जनहित का मुद्दा पूरी तरह सफाचट है। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे। वह सारे वादे ढाई साल बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण से गायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो चार प्रमुख वादे किए थे, वह आज भी अधूरे हैं। इनमें किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल, किसानों को गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपया प्रति क्विंटल, लाइली बहन योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3 हजार रुपया, घरेलू गैस सिलिंडर 450 रुपए में देने के वादे अधूरे हैं।

विधायक निधि नहीं बढ़ाने पर हंगामा

बजट भाषण के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने विधायक निधि बढ़ोतरी नहीं किए जाने के कारण बजट भाषण के दौरान हंगामा किया। बजट भाषण पर सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत होकर अपनी सीट पर बैठने के निर्देश दिए। वहीं, कांग्रेस विधायक सरकार पर कई के विरोध में खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। विरोध के दौरान कांग्रेस नेताओं ने तख्तापकड़ी हुई थीं, जिन पर लिखा था कि कर्ज बजट से ज्यादा है, फिर आप कहते हैं कि सब ठीक है।

पुलिस विभाग में 22500 पदों पर भर्ती

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पुलिसकर्मियों के लिए 11000 नए आवास बनाए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से परिहार पेंशन के अंतर्गत तलाक्युदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है।

सीएम तीर्थ दर्शन के तहत 50 करोड़

धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ मिल सके। वहीं, धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार ने 2 हजार 55 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 4 करोड़ 61 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है।

पर्यावरण के लिए 6151 करोड़

कृषि वानिकी योजना शुरू की जाएगी इससे सरकार आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। नए पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।



इंफ्रास्ट्रक्चर: 59,347 करोड़ से मिलेगी विकास को रफ्तार

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का 'इंजन' घोषित करते हुए सरकार ने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। सड़क, सिंचाई, शहरी विकास और ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से राज्य को 2047 के लक्ष्य की ओर तेज गति देने की रणनीति बनाई गई है। बजट दस्तावेज़ में स्पष्ट कहा गया है कि अधोसंरचना विकास को इस वर्ष की प्रमुख धुरी बनाया गया है। पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत निवेश (अतिरिक्त बजटीय संसाधनों सहित) का लक्ष्य रखा गया है। इससे रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार और ग्रामीण-शहरी संतुलन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूँजीगत व्यय 80,266 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। यदि अतिरिक्त बजटीय संसाधनों और पूँजीगत परियोजनाओं को जोड़ दिया जाए तो यह राशि 1,06,156 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। पिछले सालों की तुलना में यह महत्वपूर्ण वृद्धि है और यह दर्शाती है कि सरकार दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर फोकस कर रही है।

सिंचाई परियोजनाओं को मजबूती: सिंचाई के लिए 14,742 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट दस्तावेज़ के अनुसार जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावित है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित करना है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना: केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को दूर करने और सिंचाई के दायरे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे पेयजल और कृषि दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है।

1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूँजीगत निवेश का लक्ष्य रखा गया है बजट में

80266 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं पूँजीगत व्यय के लिए इस बार बजट में

14742 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सिंचाई परियोजनाओं के लिए

पीएम आवास के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान

बजट में 6 हजार 850 करोड़ रुपए का प्रावधान पीएम आवास के लिए किया गया है। इसी तरह पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 19300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल और आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। 7 लाख 95 हजार स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान। उद्यम क्रांति योजना में 16,451 युवाओं को लोन दिया गया है।

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि लाइली लक्ष्मी योजना 2.0 में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभांशित किया गया। 14 लाख 12 हजार को छात्रवृत्ति दी गई। इसके लिए 1800 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री माजरा टोला के तहत 20,900 किलोमीटर सड़क बनाने का स्ट्रेटस दिया गया है। सड़क रिपेयर के लिए 12,690 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवा परिवारों के मेट्रोपॉलिटन एरिया में बढ़ते माइग्रेशन के असर को कम करने के लिए 'संस्था छाया' प्रोग्राम शुरू किया गया है। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कॉचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उद्यम के लिए भी बड़े स्तर पर बजट का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ समुदायों के विकास के लिए 1,651 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी सुधार पर विशेष जोर दिया गया है।

'ज्ञान' से 'ज्ञानी' हुआ इस बार बजट किसान, महिला, युवा, गरीब में इंफ्रास्ट्रक्चर-इंडस्ट्री भी जुड़े

विशेष संवाददाता, भोपाल। डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र ज्ञान से आगे जाकर ज्ञानी पर फोकस रहा है। सरकार ने किसान, युवा, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें कुछ नई योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने देश

प्रदेश के विकास के लिए ज्ञान यानि कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के उद्यम को मिशन के तौर पर करने का संदेश दिया था। राज्य सरकार ने ज्ञान में दो आई और जोड़कर उसे ज्ञानी बनाया है। यानि कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को भी जोड़ दिया है। सरकार ने बजट में सीएम युवा शक्ति योजना के तहत राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुविधायुक्त स्टेडियम बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया है। सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा कि मध्यप्रदेश का युवा प्रदेश के तौर पर स्थापित हो रहा है और देश में तीसरा युवा प्रदेश है, ऐसे में युवाओं को सक्षम और रोजगारयुक्त बनाने के लिए सरकार उनके लिए अनेक योजनाओं के जरिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। युवाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा बजट के जरिए एक खाका तैयार किया गया है। बजट में राज्य में औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए जहाँ बजट राशि का प्रावधान किया गया है, तो वहीं 19,300 एकड़ जमीन भी आरक्षित की गई है। इसी तरह जनजातीय विकास के लिए भी सरकार ने 793 करोड़ की राशि बजट में समाहित की है। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांवों का विकास करने सरकार इस बजट को खर्च करेगी। विशेषकर दुर्गम और अति पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रावधान का लाभ मिलेगा। बजट में प्रदेश की बेरोजगारी दर को कम करने का भी रोडमैप बनाने के संकेत मिले हैं। सरकार चाहती है कि हर हाथ को काम मिले, इसके लिए सरकार कौशल विकास और नए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगी।

सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवंटन के तहत अगले वित्तीय वर्ष में सरकार राज्य के पात्र लोगों को 50 करोड़ की राशि खर्च कर तीर्थों के दर्शन कराएगी। धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार 2 हजार 55 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी।

नए टैक्स नहीं, पुराने में वृद्धि नहीं

इस बजट में न तो कोई नए टैक्स का प्रावधान किया गया है और न ही मौजूदा टैक्स ही बढ़ाए गए हैं। कर्मचारियों को आठवें वेतनमान के लिए भी किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। इस पर वित्त विभाग ने सफाई दी कि मामले केन्द्र का है, जब तक इसके लिए केन्द्र से किसी भी तरह के निर्देश नहीं आएं, तब तक राज्य सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगी। इसी तरह बजट में महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा आदिमजाति कल्याण विभाग की मेधावी छात्र पुरस्कार योजना और स्कूल शिक्षा विभाग की साइकिल प्रदाय जैसी योजना अगले 5 सालों तक चलने की बात भी बजट में की गई है।

संसाधन		
1.17667	1.12,137	54,505
राज्य कर से	करोड़ केन्द्रीय करों में हिस्सा	करोड़ केन्द्र से सहायता अनुदान
24,394	80,694	
करेतर राजस्व	करोड़ अन्य प्राप्ति (पूँजीगत)	

युवा शक्ति 45,358 करोड़ रुपए का प्रावधान, बीते साल की तुलना में 13 फीसदी की वृद्धि

शिक्षा और युवा: कौशल, छात्रवृत्ति और खेल को मिला बल

बजट 2026-27 में शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को विकास की धुरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 'युवा शक्ति' को बजट के मुख्य फोकस में शामिल किया गया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कौशल, शिक्षा और अवसरों के माध्यम से ही आत्मनिर्भर राज्य की नींव मजबूत होगी। बजट दस्तावेज़ के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा विभाग के प्रावधानों में वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित अनुमान 40,160 करोड़ की तुलना में 2026-27 के लिए 45,358 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह लगभग 13 फीसदी की वृद्धि है।



3,068 करोड़ अधोसंरचना और विद्यालय उन्नयन

'सादीपनि विद्यालय' के लिए 3,068 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह संकेत देता है कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय तैयार करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है इसके अतिरिक्त पीएम श्री योजना के तहत 530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे चयनित स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

986 करोड़: छात्रवृत्ति और सुविधाएं

छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 986 करोड़ का प्रावधान है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि साइकिल योजना के लिए 530 करोड़ और स्कूटी व लैपटॉप वितरण के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

715 करोड़: खेल और युवा कल्याण

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 2026-27 में 715 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुल खेल एवं युवा कल्याण मद में 815 करोड़ का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि सरकार युवाओं को खेल के माध्यम से भी अवसर देना चाहती है। इससे शिक्षण व प्रतिभा खोज को मजबूती मिलेगी।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जीरमजी के लिए 10,428 करोड़ का प्रावधान।
- वन पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- धर्म और संस्कृति के लिए 2,055 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 7 लाख 95 हजार स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता।
- 2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव।
- 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल-आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
- मात वंदना योजना के लिए 386 करोड़ रुपये का प्रावधान।



ऑफ बीट

चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस



चीन ने सोमवार को दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत दिखाई। एक कार्यक्रम में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने मार्शल आर्ट्स और डांस किया। करीब 25 रोबोट्स बच्चों के साथ तलवार भंजते, बैकलिफ्ट करते और उड़ते घुमाते हुए डांस करते दिखाई दिए। खास बात यह रही कि एक भी रोबोट गिरा नहीं। यह प्रदर्शन देख दुनिया हैरान रह गई। कई लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर रोबोट अब नाच सकते हैं और कुंग फू कर सकते हैं, तो वे और क्या कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले विस्फुल अलग था। पिछले साल रोबोट्स सिर्फ रुमाल घुमाते और साधारण हरकतें करते नजर आए थे, लेकिन एक साल में सबकुछ बदल चुका है। चीन दुनिया को खासकर अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वह तकनीक में बहुत आगे निकल चुका है। एशिया में टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी के प्रमुख जॉर्ज स्टीलर ने कहा कि जिस गाला में इन रोबोट्स ने प्रदर्शन किया।

किसी लड़की का नाड़ा खींचना, ब्रेस्ट पकड़ना रेप की कोशिश: सुप्रीम कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे रेप नहीं माना, सीजेआई ने पलटा आदेश

प्रयागराज, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचना और ब्रेस्ट पकड़ना रेप की कोशिश माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें इसे रेप की कोशिश की जगह रेप की तैयारी बताया गया था।



2021 में बच्ची के साथ तीन युवकों ने की थी छेड़खानी

कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी, 2022 को कोर्ट में शिकायत में आरोप लगाया कि 10 नवंबर, 2021 को वह 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में देवरानी के घर गई थी। उसी दिन शाम को घर लौट समय रास्ते में गांव के ही पवन, आकाश व अशोक मिल गए। पवन ने बेटी को बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने भरोसा करते हुए बाइक पर बैठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पायजामे की डोरी तोड़ दी। लड़की की चीख-पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे।

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल किया है। हम हाईकोर्ट की इस बात से सहमत नहीं हैं कि आरोप सिर्फ तैयारी तक सीमित है। आरोपियों की हरकत साफतौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करती है। पहली नजर में शिकायतकर्ता, अभियोजन ने रेप की कोशिश का मामला बना दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने 17 मार्च, 2025 को आदेश में कहा था कि ये कृत्य रेप या रेप की कोशिश की कटेगरी में नहीं आते।

हाईकोर्ट ने कहा था-पायजामे का नाड़ा तोड़ना अटेम्प्ट टू रेप नहीं: 17 मार्च, 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा-किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, पायजामे का नाड़ा तोड़ देना, जबनर उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या 'अटेम्प्ट टू रेप' का मामला नहीं बनता। यह रेप की तैयारी है। 12 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दीं।

सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, फैसले पर रोक लगाई: हाईकोर्ट के फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं व अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने विरोध जताया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले का खतम: संज्ञान लिया। 25 मार्च को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई। तत्कालीन सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की थी।

हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी: मामले पर 8 दिसंबर, 2025 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था-हम सभी हाईकोर्ट के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियां पीड़ित पर चिलिंग इफेक्ट यानी भयावह भाव डालती हैं और कई बार शिकायत प्रयास लेने जैसा दबाव भी पैदा करती हैं।

इधर, छग हाईकोर्ट ने भी दिया 'इलाहाबाद' जैसा फैसला बिना पेनिट्रेशन रेप नहीं, सिर्फ कोशिश

छग हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से जुड़े मामले में आरोपी की सजा बदलकर दुष्कर्म की कोशिश का फैसला सुनाया। रेप केस में सजा को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, अगर घटना के दौरान पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो उसे दुष्कर्म नहीं, दुष्कर्म की कोशिश माना जाएगा। कोर्ट ने आरोपी की सजा 7 साल से साढ़े तीन साल कर दी, क्योंकि मेडिकल सबूतों से पता चला कि पीड़िता की हाइमन सही सलामत थी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा, आरोपी का इरादा 'क्रिमिनल था, प्रांसिक्वशन पेनिट्रेशन साबित करने में नाकाम रहा, जो 2004 में आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप के लिए एक जरूरी हिस्सा था। धारा 376(1) के तहत सजा को बदलकर धारा 376/511 (रेप की कोशिश) कर दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

प्रांसिक्वशन के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती उसके घर से अपने घर खींच लिया, उसके कपड़े उतारे और उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोशिश की। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पीड़िता को कथित तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसके हाथ-पैर बांधे और उसके मुंह में कपड़ा दूंस दिया गया था। कुछ घंटों बाद, उसकी मां ने उसे कैद से छुड़ाया। 2005 में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 376(1) और 342 के तहत दोषी ठहराया और उसे रेप के लिए सात साल की कड़ी कैद और गलत तरीके से कैद करने के लिए छह महीने की सजा सुनाई। इस केस में अपील एक ही जरूरी कानूनी सवाल पर टिकी थी-क्या पेनिट्रेशन हुआ था?

एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो: चीनी रोबोट के प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद

गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोट ड्रोन को बताया अपना, समिट से बाहर

नई दिल्ली, जेएनएन। चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन को अपना प्रोजेक्ट बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो से बाहर कर दिया गया है। आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पब्लिसन की बिजली काटी, फिर ताला लगाकर कैमिफ्लेज कर दी गई। यह कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज कंपनी के रोबोटिक डॉग को अपनी खुद की खोज बताया था।

यूनिवर्सिटी ने माना, हमने नहीं बनाया ये डॉग

वीडियो वायरल होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा-हमने लगातार कैम्पस में बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की है, क्योंकि जब छात्र नई चीजें देखते हैं, तभी सोच विकसित होती है। और यही सोच नए रचनाकारों को जन्म देती है। हाल ही में यूनिटी से लिया गया रोबोटिक डॉग इसी सप्तर का एक हिस्सा है। यह सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई कोई मशीन नहीं है, यह चलता-फिरता क्लसरूम है। हमारे छात्र इस पर प्रयोग कर रहे हैं, इसकी क्षमताओं को परख रहे हैं और इस प्रक्रिया में ज्ञान बढ़ा रहे हैं। हम साफ कर देना चाहते हैं कि गलगोटिया ने यह रोबोटिक डॉग नहीं बनाया है और न ही कभी ऐसा दावा किया है। लेकिन हम ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही भारत में ऐसी ही टेक्नोलॉजी को डिजाइन करेंगे, उनकी इंजीनियरिंग करेंगे और उन्हें यहीं बनाएंगे।



सरकार ने देश की इमेज खराब की: कांग्रेस

इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने देश की इमेज खराब की है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। यह भारत के लिए वाकई शर्मिंदगी की बात है।

समिट में शामिल होने दिल्ली पहुंचे ब्राजीली राष्ट्रपति लूला

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिलवा बुधवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वह यहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने आए हैं। वे 18 से 22 फरवरी तक भारत में रहेंगे। यह दौरा पीएम पीएम मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। इस बार राष्ट्रपति लूला 260 कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों का दल

14 मंत्री भी साथ आए, दोनों देशों के बीच हो सकती है बड़ी डील

लेकर आए हैं। उनके साथ करीब 14 मंत्री भी पहुंचे हैं। लूला 19, 20 फरवरी को नई दिल्ली में दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। इससे इतर मर्कसुर-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर बात हो सकती है। लूला की 21 फरवरी को मोदी के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक होगी।

2 करोड़ कर्मचारियों को देंगे देगा गूगल

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम ने कहा कि हमने भारत में एआई के क्षेत्र में हो रहे काम, गूगल कैसे हमारे युवाओं के साथ काम कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की। समिट के इतर कई बैठकों का उद्देश्य एआई में भारत की लीडरशिप को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है। मोदी से मुलाकात के बाद पिचाई दिल्ली में मीडिया रिसेशन में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, गूगल कर्मयोगी भारत मिशन के तहत 2 करोड़ कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देगा।

एआई से नौकरियां दोगुनी होंगी: जितिन

केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, भारत ऐसा एआई बना सकता है, जिससे स्टार्टअप को सीधा फायदा मिले। टेक्नोलॉजी आसान, सस्ती होनी चाहिए, ताकि ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। मंत्री ने कहा कि यह चिंता स्वाभाविक है, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, शुरुआत में डर होता है कि नौकरियां कम होंगी, लेकिन इतिहास बताता है कि टेक्नोलॉजी नए अवसर भी बनाती है। उनका दावा था कि एआई से जॉब्स कम नहीं होंगी, बल्कि नए सेक्टर में रोजगार बढ़ेंगे। रेगुलेशन को लेकर उन्होंने साफ कहा कि भारत ओवर-रेगुलेशन नहीं करेगा।

10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 को चुना

नई दिल्ली, जेएनएन। चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा, जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास हैं, 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 व प.बंगाल-बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। शरद पवार, रामदास अठवले, कनिमोड़ी, तिरुचि शिवा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4

बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। **बैलट पेपर पर खास पेन से होगी वोटिंग:** आयोग ने कहा, वोट डालते समय केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से दिए गए तय मानक का चॉयलेट रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल होगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। आयोग ने कहा, चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से कराने पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ईवीएम, वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू किया है।

अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट खाना

वाशिंगटन डीसी, जेएनएन। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे हैं। ईडिपेंडेंट फ्लाइंग-ट्रैकिंग डेटा, मिलिट्री एविएशन मॉनिटरिंग ने कई एफ-22, एफ-35 और एफ-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिपोर्ट किया है। यह जानकारी अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को जिनेवा में हुई दूसरी दौर की बातचीत के दौरान सामने आई है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते से जुड़े मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, ट्रैप की तय की गई शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। फर्कस न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि बातचीत के कुछ हिस्से सकारात्मक रहे, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमत नहीं बनी है।

कटनी: स्कूल की दीवार गिरने से 5वीं के छात्र की मौत छोटी बहन हटाती रही मलबा, शिक्षक बेखबर

जागरण, कटनी। स्कूल की जर्जर दीवार की प्रशासन और स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई अनदेखी एक बच्चे की जान ले गई। जब शौचालय की इस जर्जर दीवार के गिरने से उसमें 11 साल का मायूम दब गया। मलबे में दबने से 5वीं के छात्र की मौत हो गई। शिक्षकों की लापरवाही का आलम यह कि न तो उन्हें दीवार गिरने की आवाज आई और न ही बच्चे को बचाने का हा उन्होंने कोई प्रयास किया। बच्चे की छोटी बहन ही वहां आवाज सुनकर पहुंची और नन्हे हाथों से मलबा हटाने में जुटी रही। घटना पर अब भी सहमत नहीं बनी है।



क्षेत्र के बमहंगवा शासकीय स्कूल में बुधवार को हुई। 5वीं का छात्र राजकुमार पड़ रहा है। जिला शिक्षा विभाग ने इन आरोपों मामले की जांच करने के लिए टीम का गठन कर दिया है। डीडीओ का कहना है कि जिसने भी लापरवाही की होगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिक्षकों की लापरवाही

बच्चे के परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल के शिक्षकों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के शौचालय की दीवार लंबे समय से जर्जर है। इसके गिरने और बच्चों के साथ हादसे की आशंका जताते हुए कई बार शिकायत की गई। मगर स्कूल के शिक्षकों के इसे अनजाना कर दिया। इसी का खामियाजा आज परिवार को भुगताना पड़ रहा है। जिला शिक्षा विभाग ने इन आरोपों मामले की जांच करने के लिए टीम का गठन कर दिया है। डीडीओ का कहना है कि जिसने भी लापरवाही की होगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।

आधुनिक निवेश विकल्पों के बावजूद 62 फीसदी युवा मानते हैं सोने को सबसे भरोसेमंद

पेशेवर युवा भारतीयों के निवेश में पहली पसंद बना सोना

नई दिल्ली, जेएनएन। आधुनिक वित्तीय उत्पादों की पहुंच तेजी से बढ़ने और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्मों के विस्तार के बावजूद सोना आज भी युवा भारतीयों के बीच सबसे पसंदीदा निवेश विकल्प बना हुआ है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक, 62 फीसदी युवाओं ने सोने को अपनी पहली निवेश पसंद बताया। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि बदलते आर्थिक परिवेश और नए निवेश साधनों के बावजूद पारंपरिक संपत्ति के रूप में सोने की विश्वसनीयता बरकरार है। रिस्मटन पल्स एआई सर्वे के अनुसार, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी जैसे विकल्पों की लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद जेन जेड और मिलेनियल्स अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए सोने पर अधिक भरोसा जता रहे हैं। युवा निवेशकों के बीच यह धारणा मजबूत है कि बाजार की अस्थिरता और आर्थिक

अन्य विकल्पों की ओर कम झुकाव

सिमटन पल्स एआई द्वारा किए गए इस सर्वे में 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के 5,000 उद्योगिकताओं को शामिल किया गया। जब प्रतिभागियों से पूछा गया कि यदि उनके पास आज 25,000 रुपये निवेश के लिए हों तो वे किस विकल्प को चुनेंगे, तो 61.9 फीसदी ने सोने को प्राथमिकता दी। अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में यह आंकड़ा काफी अधिक है। सर्वे में 16.6 प्रतिशत प्रतिभागियों ने म्यूचुअल फंड को चुना, जबकि 13 प्रतिशत ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) को प्राथमिकता दी। शेयर बाजार में निवेश करने वालों का प्रतिशत 6.6 रहा और केवल 1.9 प्रतिशत लोगों ने क्रिप्टोकॉर्सेसी को चुना। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जोखिम वाले निवेश साधनों की तुलना में युवा अब भी पारंपरिक और स्थिर माने जाने वाले विकल्पों को अधिक महत्व दे रहे हैं। विशेष रूप से आर्थिक अस्थिरता या बाजार में उतार-चढ़ाव के समय सोने की ओर झुकाव और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। लगभग 65.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बैंक बचत, म्यूचुअल फंड या इंडिटी की तुलना में सोना उन्हें सबसे सुरक्षित विकल्प लगता है।

पारिवारिक परंपरा का हिस्सा। पहले जहां सोना खरीदने के फैसले अक्सर परिवार के बुजुर्गों या सामाजिक परंपराओं से प्रभावित होते थे, वहीं अब युवा अपनी आर्थिक स्थिति और निवेश रणनीति के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। खरीद के पैटर्न में भी स्पष्ट बदलाव देखने को मिला है। 62 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि उनकी हालिया सोने की खरीद

5 ग्राम से कम थी। इनमें से 27.5 प्रतिशत ने 2 ग्राम से कम सोना खरीदा, जबकि 34.4 प्रतिशत ने 2 से 5 ग्राम के बीच निवेश किया। कुल मिलाकर 61.9 प्रतिशत हालिया खरीद 5 ग्राम से कम रही। जो यह संकेत देती है कि अब बड़े और एकमुश्त निवेश की बजाय छोटे और नियमित निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है।

आगे-निवेश के नए कारण

पारंपरिक शोदी-ब्याह से आगे-निवेश के नए कारण पारंपरिक रूप से भारत में सोना शायदियों, त्योहारों और पारिवारिक आयोजनों से जुड़ा रहा है। सर्वे के अनुसार अब इसकी खरीद के पीछे व्यक्तिगत और वित्तीय कारण भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। करीब 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने पहली बार सोना तब खरीदा जब उन्हें अपनी पहली सैलरी मिली या उन्होंने स्वयं आय अर्जित करनी शुरू की। वहीं 23.9 प्रतिशत लोगों ने कहा, उन्होंने निवेश के उद्देश्य से अपनी पहली सोने की खरीद की। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि युवा पीढ़ी सोने को केवल आभूषण या परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित वित्तीय योजना का हिस्सा मान रही है।

बांग्लादेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक रहमान का सख्त संदेश-माँब कल्चर बर्दाश्त नहीं

ढाका, जेएनएन। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में बुधवार को नई कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री रहमान के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट के सदस्य और सलाहकार शामिल हुए। बैठक में सरकार ने शुरुआती तौर पर 3 प्रमुख प्राथमिकताएं तय कीं और उन्हें लागू करने का निर्णय लिया। इन प्राथमिकताओं में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण, कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार और बिजली व ऊर्जा की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। बैठक समाप्त होने के बाद नए गृह मंत्री सलाहद्वारा अहमद और सूचना एवं प्रसारण मंत्री जहूरुद्दीन स्वपन ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। गृह मंत्री ने अहमद ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक बनाए रखना तथा बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में किसी तरह की समस्या न होने देना सरकार की प्राथमिकता है।



सर्वे

नई दिल्ली, जेएनएन। आधुनिक वित्तीय उत्पादों की पहुंच तेजी से बढ़ने और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्मों के विस्तार के बावजूद सोना आज भी युवा भारतीयों के बीच सबसे पसंदीदा निवेश विकल्प बना हुआ है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक, 62 फीसदी युवाओं ने सोने को अपनी पहली निवेश पसंद बताया। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि बदलते आर्थिक परिवेश और नए निवेश साधनों के बावजूद पारंपरिक संपत्ति के रूप में सोने की विश्वसनीयता बरकरार है। रिस्मटन पल्स एआई सर्वे के अनुसार, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी जैसे विकल्पों की लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद जेन जेड और मिलेनियल्स अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए सोने पर अधिक भरोसा जता रहे हैं। युवा निवेशकों के बीच यह धारणा मजबूत है कि बाजार की अस्थिरता और आर्थिक





नगर में आज

वार्षिक टेक्नो-कल्चरल उत्सव

- स्थान: मैनिट सिविल ऑडिटोरियम
- समय: दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक

संगीत संध्या

- स्थान: रवीन्द्र भवन
- समय: शाम 6 बजे से

माह का प्रदर्श

- स्थान: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी स्मृति संग्रहालय
- समय: शाम 4:00 बजे
- आयोजक: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

चित्र प्रदर्शनी

- समय: दोपहर 12:00 बजे से
- स्थान: मप जनजातीय संग्रहालय

संक्षिप्त खबरें

भद्रभद्रा रोड पर आज 6 घंटे तक की बिजली कटौती

जागरण संवाददाता, भोपाल। गुरुवार को शहर के कोकता और भद्रभद्रा रोड स्थित क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ क्षेत्रों में भी बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार आज कोकता स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना मल्ली, डायमंड सिटी, कस्तूर कोर्टघाट, राजधानी परिसर और आसपास के इलाकों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं भद्रभद्रा रोड स्थित पुलिस वायरलेस, क्राइम ब्रांच, सह्याद्रि परिसर, सीएसडी कालोनी, 25वीं बटालियन, पुलिस रेडियो कालोनी, न्यू पुलिस क्वार्टर, मन्स्य महासंघ, प्रेमपुरा, सयाजी होटल और वन विहार नेशनल पार्क व आसपास के इलाकों में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। नेहरू नगर रोड स्थित पुलिस हाउसिंग, फॉरसिक लैब, गौतम नगर, करुणाधाम आश्रम, प्रगति परिसर, कम्पट प्लाजा, गोमती परिसर, डीके सुरभि, मनीषा अस्पताल, जैन टावर, नेहरू नगर रोड, आईआईएफएम और आसपास के इलाकों में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बिजली कटौती सप्लाई बाधित रहेगी। इसके अलावा शहर के बड़वई व कोरल वुड कालोनी में भी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बर्डिया फूड, ध्रुव पेरटीसाइड, जीके इंडस्ट्री, एयरटेक इंडस्ट्री, मेटल जंक्शन, हाई टेक इंजीनियरिंग, टेस्टला, मनीत इंडस्ट्री, स्वारिक्त रबर, फिटवेल कॉर्पोरेशन व आसपास बिजली सप्लाई बाधित रहेगी।

17 साल की नाबालिग से ठेकेदार ने किया दुष्कर्म

जागरण, भोपाल। पिपलानी थाना क्षेत्र में ठेकेदार ने नाबालिग से सात महीने तक दुष्कर्म किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग अपने पिता के अलग होने के बाद मां के साथ पिपलानी इलाके में रह रही थी। उसके पिता छिंदवाड़ा में रहते हैं। पांच साल पहले काम के दौरान उसकी मां की पहचान ठेकेदार अजय कुमार तिवारी उर्फ मंदेश से हुई। जो बिहार का रहने वाला है। आरोपी ज्यादातर समय उनके घर में ही रहता था। 20 अगस्त 2025 को आरोपी ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और फिर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। सोमवार को नाबालिग के पेट में दर्द होने पर मां उसे अस्पताल लेकर पहुंची। जहां डॉक्टरों ने नाबालिग को 24 हफ्ते का गर्भवती बताया। मां के पछुने पर बेटी ने आपबीती सुनाई। बाद में पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मैनिट के 'नायमैक 3.0' में दिखा तकनीक और युवा प्रतिभा का संगम

जागरण, भोपाल। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) का सिविल ऑडिटोरियम बुधवार को युवा ऊर्जा और नवाचार की रोशनी से जगमगा उठा। अवसर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नॉलाजी (ट्रिपल आईटी) के वार्षिक टेक्नो-कल्चरल उत्सव 'नायमैक 3.0' का भव्य शुभारंभ। इस महोत्सव ने पहले ही दिन तकनीकी कौशल और सांस्कृतिक विविधता की अनूठी मिसाल पेश की। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्थान के निदेशक ने कहा कि आज के दौर में केवल तकनीकी डिग्री काफी नहीं है, बल्कि तकनीकी उत्कृष्टता के साथ नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और मजबूत चरित्र का होना अनिवार्य है। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के लिए कम्प्यूटिकेशन रिक्त और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी आधुनिक दिशाओं को अपनाते पर विशेष जोर दिया। इस उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण संस्थान की



नई शोध पत्रिका 'वायुना' का विमोचन रहा। पत्रिका की संपादक डॉ. नेहा सिंह ने बताया कि यह पत्रिका छात्रों के शोध, विकास और नए आविष्कारों को एक वैश्विक मंच प्रदान करेगी। सांस्कृतिक खंड में अध्यात्म और समाज का सुंदर मेल दिखा। जहां 'कृष्ण चेतना' पर आधारित नाटक ने विनम्रता और शांति का संदेश दिया, वहीं नुक्रड़ नाटक के माध्यम से नागरिक कर्तव्यों के प्रति युवाओं को जागरूक किया गया।

राजधानी में 36 घंटे में 35 सायबर ठगी की एफआईआर, 2.14 करोड़ का हुआ फ्रॉड

केंद्रीय गृह मंत्रालय की फटकार के बाद जागा स्टेट सायबर, 18 एफआईआर और दर्ज होना बाकी, पुलिस जांच में जुटी

चार माह में किए सभी फ्रॉड

क्राइम रिपोर्ट, भोपाल। राजधानी में 36 घंटे के अंदर 35 सायबर ठगी एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें सवा दो करोड़ का फ्रॉड हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की फटकार के बाद स्टेट सायबर जागा और एफ आई आर दर्ज होना शुरू हो गईं। अभी 18 और एफआईआर दर्ज होना बाकी है। स्टेट सायबर सेल ने जांच के नाम इन शिकायतों को दबा लिया था। जबकि उन्हें जीरो पर एफआईआर दर्ज कर संबंधित थानों को भेजनी थी। दरअसल, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय हेल्प लाइन नंबर 1930 के जरिए ही आनलाइन एफआईआर की सुविधा दी थी। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य सायबर सेल को इस आदेश की सुध नहीं थी। ऐसे में शिकायतें आती गईं और इनकी संख्या अधिक हो गई। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को लगी तो उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गईं।

जागकारी के मुताबिक, 36 घंटे के अंदर दर्ज हुई 35 एफआईआर में सर्वाधिक भोपाल के जोन-टू में 15 केस दर्ज हुए। इसमें सबसे ज्यादा बागसेवनिया में 7 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके बाद जोन-वन में 9 केस दर्ज हुए। इसके अलावा जोन-फोर में 5 सायबर फ्रॉड के प्रकरण दर्ज हुए। सभी मामलों में राज्य सायबर की ओर से जीरो पर एफआईआर दर्ज कर थानों को भेजी गई है। थाना पुलिस अब पीड़ितों को फोन लगाकर उनके साथ हुए फर्जीवाड़े के संबंध में पूछताछ के साथ दस्तावेज जुटा रही है। यह सायबर फ्रॉड निवेश, नौकरी, डेबिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, बिजली कनेक्शन काटने की धमकी आदि के नाम पर किए गए हैं। यह सभी फ्रॉड सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 यानी चार महीने में किए गए।

लाइक और सब्सक्राइब के नाम पर 29 लाख एंटे

मिसरोद इलाके के कोरल वुड कालोनी में रहने वाले सुप्रीत कुमार गड्डू (30) से 29 लाख की आनलाइन ठगी की गई। जालसाज ने उन्हें लिंक भेजी। बताया कि आईएनबीडी मूवी को लाइक और सब्सक्राइब करने पर पैसा मिलेगा। सुप्रीत ने वैसा ही किया तो उन्होंने 2 हजार से 30 हजार रुपए का मुनाफा कमाया। लालच में आने के बाद सुप्रीत पैसा निवेश करते गए। उनके वंचुअल खाते में करोड़ों रुपए दिख रहे थे। उन्होंने यह पैसा निकालना चाहा तो उनसे 29 लाख रुपए की मांग की गई। सुप्रीत ने यह पैसा जमा किया तो सभी के मोबाइल बंद गए। उनका खाता डिलीट कर दिया गया। सुप्रीत शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं।

शिवम कटारिया से 23 लाख ठगे

इसी तरह कमला नगर में 23 लाख रुपए का ठगी शिवम कटारिया के साथ हुई। हबीबगंज में अनुज बागड़े से 15 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर एंटे लिए। इसी तरह से हरीश हासवानी, आमीन खान, राजेश लोकवानी, लक्ष्मी, वसीम हुसैन अंसारी, शैलेंद्र पाराशर, तनु सिंह, रोहित ताम्रकार, सुनीता, रमेश चंद्र शाक्य, स्वप्निल पटेल, प्रियंका समायरा और पन्ना उमेरिया सहित कई लोगों से आनलाइन ठगी की गई।

निवेश के नाम पर 51 लाख का चूना

सबसे बड़ी ठगी बागसेवनिया थाना इलाके में 51 लाख रुपए की सामने आई है। यह ठगी साकेत नगर निवासी राजेश जैन के साथ अक्टूबर 2025 में हुई। 20 अक्टूबर को राजेश जैन को अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक वाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा गया। जोकि यश सिक्कारिटीज के नाम से था। इस ग्रुप में लोगों द्वारा लगातार कुछ ऑनलाइन निवेश किया। शुरुआत में उन्हें मुनाफा दिखाया गया। उन्होंने भरोसा हो गया। उक्त व्यक्ति ने वाट्सएप पर एक लिंक भेजी। राजेश को ज्वाइन करने को कहा। राजेश ने आईडी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद राजेश निवेश करते गए और उन्हें मुनाफा बताया गया। इसमें से राजेश ने 60 हजार रुपए निकाले। इसके बाद राजेश ने कई बार में 35 लाख रुपए जमा किए। उन्हें मुनाफा दिखाया गया। राजेश ने पैसे निकालने को बोला तो उनसे इतनी ही राशि केपिटल गेन टैक्स के रूप में जमा करने को बोला गया। तब उन्हें लगा उनके साथ ठगी हो गई। इन थानों में दर्ज हुई एफआईआर: थाना ऐशबाग, हबीबगंज, मिसरोद, बागसेवनिया, कोलार रोड, अशोका गार्डन, कमला नगर, पिपलानी, अवधपुरी, बैरागढ़, शाहजहाँनाबाद, निशातपुरा और गांधी नगर में आनलाइन धोखाधड़ी के केस दर्ज हुए हैं। अभी दो दर्जन से ज्यादा प्रकरण और भी दर्ज होना बाकी है।

शातिर रजिया ने रैकी कर की थी छह लाख की चोरी, फुटेज से पकड़ाई

क्राइम रिपोर्ट, भोपाल। टीटीनगर इलाके में गमले के बगल में टंगी चाबी चोरी कर सूने घर में छह लाख की चोरी की थी। पुलिस ने फुटेज खंगाले तो वह पकड़ी गई। महिला शातिर चोर है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 26 अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उसकी स्कूटी जब्त की है। टीटीनगर थाना प्रभारी गौरव दोहर ने बताया कि 53 वर्षीय मंगला बंसोडे पति नारायण बंसोडे निवासी कम्प्यूनिटी हॉल के सामने बाणगंगा नार्थ टीटीनगर ने 16 फरवरी को चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि 15 फरवरी की दोपहर दो बजे वह घर पर ताला लगाकर शिव बारात में शामिल होने के लिए शिव मंदिर चली गई थीं। शिव बारात से वह तीन बजे वापस लौटी तो बेटे से चाबी ली। रात साढ़े दस बजे पैसे निकालने के लिए अलमारी खोली तो उसमें रखे तीन लाख रुपए, सोने का मंगलसूत्र, सोने की चेन, कान की बाली, लाकेट व चांदी का गुच्छा गायब था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो संदेही महिला दिखी। उसकी पहचान रजिया खान (44) पति हसन खान निवासी जनता क्वार्टर ऐशबाग के रूप में हुई।

मौसम का बदला मिजाज, मालवा-निमाड़ और ग्वालियर-चंबल में हुई बारिश

11 जिलों में ओला-बिजली का अलर्ट, बादलों और तेज हवा से गिरा पारा



मुख्य संवाददाता, भोपाल। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। बुधवार को राजधानी भोपाल समेत अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलीं। इससे पहले दो दिनों से प्रदेश में धूप खिली थी और अधिकतम तापमान 31 डिग्री के ऊपर चला गया था। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में स्थित एक सिस्टम की वजह से कई जिलों में बारिश और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, इससे तापमान में भी एक से दो डिग्री की कमी आने की संभावना है। राजधानी में बुधवार शाम 25 से 28 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली। मौसम विभाग के अनुसार मौसम का यह रुख गुरुवार को भी बना रहेगा और शुक्रवार से फिर तापमान में इजाफा होगा।

आज भी कई शहरों में बारिश की संभावना : मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में बुधवार को बारिश हुई। इनमें झाबुआ और रतलाम जिलों में अन्य स्थानों की तुलना में अधिक बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा झाबुआ में 3.6 मिमी और रतलाम शहर में 3.0 मिमी रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा रतलाम के आलोट, जावरा एवं उच्चैन के खाचरोद में 1 मिमी और बड़वानी शहर में 0.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा ग्वालियर एवं श्योपुर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के ग्वालियर-चंबल और मालवा अंचल के कई जिलों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी में ओलावृष्टि के आसार हैं, जबकि नीमच, मंडसौर, आगर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, गुना और शिवपुरी में तेज हवा और गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है।

कल से खिलेगी धूप

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश के उत्तरी इलाकों जैसे ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, शिवपुरी, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद शुक्रवार से पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और विंड स्पीड भी घटकर 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। इससे तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कोई सिस्टम भी एक्टिव नहीं रहेगा, जिससे प्रदेश में गर्मी के दौर की शुरुआत हो जाएगी।

The banker to every Indian brings power to every Indian

Download now

For assistance, call 1800 1234 | 2100

More personalised

More secure

Always with you

The all-new Yono is here



खुला मंच

गलगोटिया मोहल्ले में पहुंचा चीन का कुत्ता

मुकेश नेमा

दिल्ली एआई समिट के दौरान लोगों ने एक चार पैरों वाला रोबोट कुत्ता देखा। ग्रेटर नोयडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने शाबाशी ली इसे बनाने की। पर कुछ जलकुक्डों ने शाबाशी कि ये कुत्ता चीनी है। बवाल मचा,चीनी भी हँसे और गलगोटियों को मजबूरन इस कुत्ते की वल्टियत से इनकार करना पड़ा। लोगों को लगा ये उनकी किचिरी करने का एक और मूकौ का है। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। गलगोटियं को बेइज्जत किया जाना सरासर गलत बात। चीन का यह दावा कि ये कुत्ता उनका है, खारिज कर दिए जाने लायक है। कुत्ते हर जगह एक से होते है। सभी के चार पांव ,दो कान और एक पूँछ होती है जो मालिक को देख हिलती है और खुद से जबर को देख पाँवों के नीचे घुस जाती है। कुत्ता बिरिकट खिलाने वाले के पैर चाटता है और कमजोर पर भौंकता है। ऐसे मे कुत्ता कुत्ता होता है। कुत्ता सार्वभौमिक प्राणी है और भौं भौं अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ऐसे मे कोई एक देश उन पर अपना दावा ठेके ये बस हँसी की बात है।

इस बात को न कहने की कोई वजह नही कि ये कुत्ता गलगोटियो ने ही बनाया है। हम कुत्ता प्रेमी देश है। फायदा हो तो कोई भी ,कभी भी कुत्ता होने के लिए तैयार है। हम हैसियत पाते ही सामने वाले को कुत्ता बनाने में फख महसूस करते हैं। ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि ये कुत्ता स्वदेशी है और चीनी झूठ बोल रहे हैं।

और फिर यदि ये कुत्ता चीन का हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? इस कुत्ते को लेकर चीन की हायलैवा का भी कोई मतलब नही। यदि उन्हें अपने कुत्ते की इतनी ही चिंता थी तो बांध कर रखना था उसे। अब आपका बिना पड़े, बिना चैन का कुत्ता भटकता हुआ गलगोटियो के मोहल्ले में पहुंच गया। उन्होंने पाल लिया उसे। शेरु टॉमी जैसे नाम रख दिया उसका तो इसमें गलत क्या है? चीन खुद माहिर रहा है ऐसा करने में। हम तो सदियों से ऐसा ही करते आए हैं। अब एआई के इस जमाने में हमसे अपनी आदतें बदल लेने की उम्मीद रखना ठीक बात नहीं है।

गलगोटिए पसंद है मुझे। वो काबिल हिम्मती और मेहनती है। कुछ वक्त पहले इस यूनिवर्सिटी के होनहार लड़के हाथों मे बोर्डों लिए सड़कों पर देखे गए थे। लोगों ने पूछा उनसे भैया भरी धूप मे मारे मारे क्यों फिर रहे हो। पर वो न बोर्ड पर लिखे नारे पढ़ सके न ये बता सके कि उनके जुलूस का मकसद क्या है। ऐसे में हमें ये बात बेझिझक मान लेना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी कुत्ता बनाने की विधिपंड है। ये कुत्ता भी गलगोटियों ने ही बनाया है और चीन बेवजह गाल बजा रहा है।

जागरण विचार

अमेरिका एआई आधारित सुरक्षा व्यवस्था में भी कर रहा दुनिया का नेतृत्व

सैन्य क्षमता भी बढ़ रही है एआई से

राज शुक्ला

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी तकनीक अब सैन्य क्षेत्र में भी पीढ़ीगत बदलाव का वाहक बन गई है। यह सामरिक क्षमताओं को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। हम फिलहाल एआई, साइबर, क्रांटेम जैसी प्रौद्योगिकी के तुफान से गुजर रहे हैं, जिसकी जद में वैश्विक व्यवस्था और सुरक्षा, दोनों हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं।

यूक्रेन में अमेरिका की एआई कंपनी पैलाटिर ने एआई पर आधारित गोथम कमांड और कंट्रोल सॉफ्टवेयर तैनात किया है, जो सैटेलाइट डाटा, सोशल मीडिया पोस्ट, सैनिकों के ‘वाइड एरिया नेटवर्क’, यानी डब्ल्यूएन उपकरण, रेडियो फ्रिक्वेंसी आदि सबका विश्लेषण करता है और करीब 1,000 किलोमीटर लंबी उसकी सरहद की रक्षा करता है। यह सुरक्षा तंत्र इस कदर मजबूत है कि सीमा पर कोई भी हरकत हुई, तो युसपैट्रिक की पहचान करने से लेकर ढेर करने में उसे सिर्फ छह से सात मिनट का वक्त लगता है। यह एआई तकनीक पर आधारित है और ड्रोन से लैस भी। भारत में भी इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की मांग गलत नहीं है, खास तौर से नियंत्रण रेखा (एलओसी) और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर। इसके लिए एआई, ड्रोन, ग्रीडी प्रिंटिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आदि सबका ‘कोलाज’ बना होगा। यह इसलिए भी जरूरी है कि यदि मैक 6 या मैक 7 की गति से कोई हाइपरसोनिक मिसाइल हमारी सीमा की तरफ बढ़ रही हो, जो एआई की मदद से स्वतः लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम हो, तो मानव संचालित गति से उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, बल्कि एआई युद्ध उपकरणों से ही हम माकूल जवाब दे सकते हैं।

हम दो विकल्पों की ओर बढ़ सकते हैं। एक, एआई सक्षम तकनीक में इंसात ‘लूप’ में रहे, यानी फैसले लेने की प्रक्रिया में इंसानी दखल हो, और दूसरा- तकनीक में कोई मानवीय हस्तक्षेप न रहे। मेरा मानना है कि जब आक्रमण और बचाव के बीच चुन होती है, तब इंसान अगर जवाबी प्रक्रिया से बाहर रहे, तो प्रतिक्रिया कहीं अधिक तेज हो सकेगी। इससे जवाबी हमले कहीं अधिक मारक और सफे हुए होंगे।

जोहिर है एआई का फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अमेरिका का उदाहरण देखिए। उसने अपने दो कमान चुने- यूनाइटेड स्टेट्स इंडो-पैसिफिक कमांड (इंडोपैसिफ) और यूरोपीय कमान (ईयूकॉम)। इनके लिए उसने लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने का अनुबंध किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एजेंटिक एआई का अनुबंध स्केल एआई कंपनी के साथ और डिम्प्यून एआई का ठेका दिया एंड्रुलिर कंपनी को। तीनों एआई

प्रत्यर्पण सिंधु

मौजूदा हालात में हसीना का प्रत्यर्पण एक यक्ष प्रश्न

पुष्परंजन

भारत ने आम तौर पर शरणार्थियों को वापस न भेजने (नॉन-रिफाउलमेंट) की नीति अपनाई हुई है। इसी नीति के तहत, दलाई लामा जैसे प्रमुख राजनीतिक शरणार्थियों को ऐतिहासिक रूप से संरक्षण दिया गया है। हालांकि, भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

शेख हसीना, जो 5 अगस्त, 2024 को हिंसक प्रदर्शनकारियों से जान बचाते हुए ढाका से गाजियाबाद के लिए एक सीक्रेट फ्लाइट से भागी थीं, अभी फांसी से दूर हैं, और नई दिल्ली निर्वासन में रह रही हैं। शेख हसीना का सवाल विक्रम और बेताल की तरह मोदी सरकार के कंधे पर सवार हैं। यूफि प्रधापमंत्री मोदी को ‘एआई समिट’ में उपस्थित रहना था, इसलिए ढाका में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष नरम बिड़ला को भेजा। बांग्लादेश की तरफ से उन्हें सौंपने के बार-बार अनुरोध के बावजूद भारत में हसीना की मौजूदगी पिछले 18 महीनों में दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह रही है।

भले ही भारत, ढाका के साथ ‘पोस्ट हसीना पार्टनरशिप’ बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा, कि वे ऐसे हालात की कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा का सामना करने के लिए बांग्लादेश को सौंप दे। ढाका में रह चुके भारत के पूर्व हाई कमिश्नर पिनार्क चरन चक्रवर्ती ने कहा, ‘नई दिल्ली उन्हें मौत की तरफ कैसे धकेल सकती है?’ हसीना, बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं, वो शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी को लड़ाई का नेतृत्व किया था। शेख हसीना कोई पहली बार भारत में शरणगत नहीं हुईं हैं। 15 अगस्त, 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक

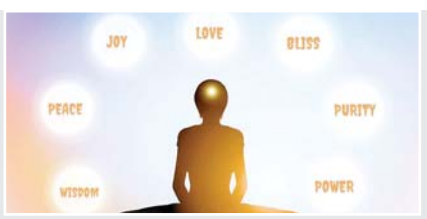


शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में उनके धानमंडी स्थित घर पर मिलिट्री तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनकी पत्नी, तीन बेटे और दूसरे रिश्तेदार मारे गए थे। उनकी दो बेटियां संयोगवश बच गयीं, जो घटना के समय जर्मनी में थीं। उनमें एक शेख हसीना और दूसरी शेख रेहाना थीं। हसीना के पास अपने पति एमए वाजेद मियां के साथ भारत में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वर्ष 1975 से 1981 तक वे सभी दिल्ली के पंडारा रोड में एक नकली पहचान के साथ रहे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार, हसीना के ‘निर्वासन पार्ट-टू’ को लेकर दुविधा में है। हसीना ने 2022 के इंटरव्यू में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद के पलों को याद करते हुए कहा, ‘मिरेज इंदिरा गांधी ने तुरंत सूचना भेजी, कि वह हमें सुरक्षा और पनाह देना चाहती हैं।’ दिल्ली आने के बाद, हसीना इंदिरा गांधी से मिलीं, तभी उन्हें अपने परिवार के 18 सदस्यों की हत्या के बारे में पता चला। हसीना ने 2022 में बताया, ‘इंदिरा गांधी ने हमारे लिए सारे इंतजाम किए। मेरे पति के लिए नौकरी भी।’ दिल्ली में हसीना पहले 56 रिंग रोड, लाजपत नगर-3 में रहती थीं, फिर दिल्ली के पंडारा रोड के घर में शिफट हो गईं। छह साल बाद, 17 मई, 1981 को, हसीना

जीवन दर्शन

अन्वेषण केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया भी है। स्वभाव, जिज्ञासा, प्रतिभा और अपनी करुणा को पहचानना भी अन्वेषण का ही रूप है। क्षितिज कोई सीमा नहीं, वह तो आपको आगे बुलाने वाला संकेत मात्र है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं है, बल्कि अपनी अपूर्ण संभावनाओं का बोध होता है। समय के प्रवाह में जब वर्ष बीत जाते हैं, तब यह एहसास भीतर कहीं चुपने लगता है कि भय ने हमें कितना रोके रखा, संकोच ने हमारे लिए कितने द्वार बंद कर दिए, और सुविधा ने हमारे व्यक्तित्व को कितना सीमित बना दिया। सुरक्षित बंदरगाह जीवन में आवश्यक अवश्य है, लेकिन वह अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। यदि जहाज किनारे से बंधा रह जाए, तो वह सुरक्षित तो रहेगा, पर अपने अस्तित्व का उद्देश्य कभी नहीं जान पाएगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य केवल सुरक्षा के घेरे में जीवन बिताए, तो वह अपनी क्षमताओं के अथाह महासागर से अनभिज्ञ ही रह जाता है। रिसियां खोलना भीतर जमे बंधनों से मुक्त होने का आह्वान है। यह उन शंकाओं को त्यागने का साहस है, जो बार-बार कहतीं हैं कि अभी समय अनुकूल

अन्वेषण की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से करें



नहीं, अभी तैयारी अधूरी है, अभी परिस्थिति साथ नहीं दे रही। जीवन में तुफान भी आएंगे, दिशाएं भी बदलेंगी, और कभी-कभी मार्ग धुंधला भी पड़ जाएगा, लेकिन इन्हीं अनुभवों की अग्नि में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन में अरुकूल परिस्थितियां स्थिर खड़े रहने वालों को नहीं, आगे बढ़ने वालों को सहारा देती हैं। अन्वेषण केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया भी है। अपने स्वभाव, अपनी जिज्ञासा, अपनी प्रतिभा और अपनी करुणा को पहचानना भी अन्वेषण का ही रूप है। जब मनुष्य स्वयं को खोज लेता है, तब उसके लिए संसार की सीमाएं स्वतः विस्तृत हो जाती हैं। स्वप्न देखिए, किंतु केवल नींद में नहीं, जागृत चेतना के स्वप्न। वे स्वप्न जो आपको चैन से बैठने न दें, जो आपको साधारणता से असंतुष्ट रखें, और जो

दैनिक जागरण

www.dainikjagranmpcg.com

संस्थापक ▶ **गुरुदेव गुप्त**

संपादकीय

युवाओं से देश को एआई का हब बनाने की उम्मीद

भारत ने बदलती वैश्विक हवा की दिशा-दशा को पहचानते हुए सबसे बड़ी एआई समिट आयोजित कराने का फैसला किया। समिट शुरू होते ही उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन की सार्थकता का पता इस बात से चलता है कि इसमें सौ बड़ी कंपनियों के सीईओ, बीस के करीब देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 135 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं।

हाल के वर्षों में, दुनिया के सबसे ज्यादा युवाओं के देश भारत में एआई को लेकर जिस तरह का उत्साह व जुनून देखने को मिल रहा है, उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वो देश को दुनिया में एआई का हब बना ही देगा। वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एआई भारत में आम लोगों के जीवन में बदलाव की वाहक बने। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई भारत समेत दुनिया के देशों में आज सुशासन, विकास व नागरिक सेवाओं के बेहतर निस्तारण में कारगर भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के देश हमारी ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि भारत द्वारा विकसित एआई के दिशा-निर्देश और नीतियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये मददगार साबित होंगी। आज दुनिया में विकसित व धनी देश एआई को अपनी संकीर्ण आर्थिक व राजनीतिक हितों की पूर्ति का साधन बना रहे हैं, उससे गरीब व विकासशील देशों में असुरक्षाबोध पैदा हो रहा है।

यह सुखद ही है कि देश की राजधानी दिल्ली पांच दिन तक दुनिया में एआई कैम्पिटल बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर, 20 फरवरी तक भारत मंडपम में आयोजित की जा रही पांच दिवसीय इंडिया समिट में करीब तीन लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, इस आयोजन की सार्थकता व सफलता को ही उजागर करता है। इसमें दो राय नहीं है कि हाल के वर्षों मे भारत ने खुद को एक एआई पावर हाउस के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। साथ ही विशाल डाटा संसाधन के साथ ही एआई वर्क फोर्स को भी तैयार किया है। निस्संदेह, इंडिया समिट तकनीकी क्रांति के बीच नई संभावनाओं को तलाशने की भारत की सकारात्मक पहल है। विश्वास किया जा रहा है कि इस सम्मेलन के जरिये भारत दुनिया में एआई को जवाबदेह, स्थायी और समावेशी तकनीक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगा।

इसमें दो राय नहीं कि हाल के वर्षों में एआई की स्वीकार्यता व कारोबार तेजी से बढ़ा है। लेकिन विडंबना यह है कि तमाम धनी राष्ट्रों में इस तकनीक को अपना जित्र बनाने की होड़ लगी है। जो कालांतर दुनिया में पहले से ही व्याप्त आर्थिक असमानता को और ही बढ़ाएगा। सही मायनों में जरूरी है कि एआई का उपयोग लोक्तान्त्रिक तरीके से नैतिकतापूर्ण ढंग से किया जाए। विश्वास किया जाना चाहिए कि इंडिया समिट में दुनिया के देश एआई तकनीक के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी मुंथन करेंगे। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एआई वैसी से दुनिया में विस्तार तो पा रही है, मगर यह तकनीक मानव जीवन के लिये कई तरह के खतरे भी पैदा कर रही है। हाल के वर्षों में दुनिया में एआई के दुरुपयोग के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। जाहिर है इसके उपयोगकर्ताओं में इसको लेकर भरोसा कायम रहना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इंडिया समिट में एआई की विश्वसनीयता बनाने की दिशा में कोई सार्थक पहल होगी। जरूरी है कि एआई का कारोबार करने वाली कंपनियों की जवाबदेही भी तय की जाए। वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां श्रमप्रधान कार्य-संस्कृति रही है और फिलहाल बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है, वहां एआई नौकरी देने वाली हो, न कि नौकरी खाने वाली। एआई के विस्तार से परंपरागत नौकरियों पर संकट नहीं आना चाहिए। निस्संदेह, युवाओं के देश भारत में एआई के प्रति जागरूकता व जुनून पैदा करने के लिये युद्ध स्तर पर पहल की जानी चाहिए। ताकि आने वाले वर्षों में हम भारत को दुनिया का एआई हब बनते हुए देख सकें।

प्रसंगवश

रेलवे की खाने की थाली में भरोसे की कमी

सरकार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 2024–25 के दौरान खाने-पीने के सामान की खराब गुणवत्ता के संबंध में 6,645 शिकायतें मिलीं। जबकि 2021 से अगले चार वर्षों में रेलवे को इस तरह की कुल 19,174 शिकायतें मिलीं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक औसत रूप से हर रोज पैंतीस से ज्यादा लोग रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान दिए जाने वाले खराब खाने को लेकर शिकायत करते हैं।

भारतीय रेलवे के बारे में अक्सर यह दावा किया जाता है कि इसके समग्र संचालन को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवा के समकक्ष बनाया जाएगा। मगर हकीकत यह है कि हादसों, सफर के दौरान निर्धारित समय पर गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने से लेकर ट्रेन के भीतर साफ-सफाई और खानपान के मामलों में कई बार स्थिति बेहद दयनीय और खराब दिखती है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिन ट्रेनों को विशेष सुविधा वाला बताया जाता है, उनमें परोसा गया भोजन भी अक्सर खराब निकल जाता है और यात्री ठगा हुआ महसूस करते हैं। खाने में तिलचूड़, हलदी, दूसरे कौड़ों या अखाद्य वस्तुओं के मिसले को शिकायतें लगाता सामने आ रही हैं। भोजन की सजा और तय कीमतों से ज्यादा राशि वसूलने की समस्या भी आम देखी जा सकती है।

सवाल है कि अगर उच्च गुणवत्ता और सेवा का दावा करके खाने-पीने के मामले में भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसे कैसे देखा जाएगा। सफर के दौरान यात्री थोड़ी सुविधा के लिए ट्रेन में मिलने वाला खाना पैसा चुका कर लेना चाहते हैं। कई ट्रेनों में सफर के दौरान टिकट के साथ खाने-पीने के सामान के लिए राशि चुकाने का भी विकल्प है। मगर विडंबना यह है कि पूरी कीमत चुकाने के बावजूद कई लोगों की थाली में ऐसा खाना होता है, जिसे यात्री नहीं जा सकता। ट्रेनों में मिलने वाले खराब खाने को लेकर आए दिन शिकायतें आती रहती हैं और कई बार विवाद भी होते हैं। ऐसी खबरें भी सामने आईं, जिनमें भोजन के खराब होने पर आपत्ति जताने पर ट्रेन में मौजूद कर्मियों ने यात्री से दुर्व्यवहार किया।

खुद सरकार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 2024–25 के दौरान खाने-पीने के सामान की खराब गुणवत्ता के संबंध में 6,645 शिकायतें मिलीं। जबकि 2021 से अगले चार वर्षों में रेलवे को इस तरह की कुल 19,174 शिकायतें मिलीं। ऐसे भी मामले होंगे, जिनमें किसी यात्री को खराब भोजन मिला, लेकिन उसने औपचारिक शिकायत नहीं की।

हालांकि रेल महकमे में कहने को एक बांया है, जिसके तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजाइन किए गए रसोई से खाना बनवाने और ट्रेनों तक पहुंचाने से लेकर खाना बनाने पर निगरानी, खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक की तैनाती और अच्छी सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने का दावा किया जाता है। इसके अलावा, अगर खाने में अस्वच्छता या मिलावट पाई जाती है, खाना खराब हो, तो यात्री शिकायत करते हैं। कई मामलों में कार्रवाई भी होती है, जिसमें जुर्माना लगाया, अनुशासनात्मक कार्रवाई, काउंसलिंग करना और चेतावनी देना शामिल है।

खराब खाने की शिकायत के बाद भोजन की आपूर्ति करने वालों पर जुर्माना लगाने की खबरें आती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर सब पहले की तरह चलता रहता है। सवाल है कि रेल मंत्रालय इसमें सुधार को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता कि ट्रेन में मिलने वाले भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर यात्री पूरी तरह आश्वस्त रहे।

अगर रेलवे के लिए अपने तंत्र के तहत स्वच्छ भोजन मुहैया कराना संभव नहीं है, तो ट्रेनों में खाना देने का ठेका अलग-अलग कंपनियों को देने और उसमें बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा को व्यवस्था बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती?



रलोक

न हि देहमृता शक्त्यं त्यक्तुं कर्माप्यशेषत।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥

भावार्थ

जो शरीर धारण किए हुए हैं, वे समस्त कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जो केवल कर्मफल का त्याग करता है, वही सच्चा संन्यासी कहलाता है।

भोपाल को मिली 143 करोड़ रुपए की 18 सड़कें, इनमें से आठ शहर में बनेंगी

पिछली बार से आधी सड़कें भी नहीं मिलीं, बजट भी एक तिहाई हुआ

कहां से कहां तक (शहरी सड़कें)	लंबाई	खर्च होने वाली राशि
बरखेड़ीकलां से बरखेड़ीखुर्द	2 किमी	8 करोड़
से वास्तु विहार कॉलोनी	4.50 किमी आंतरिक मार्ग	7.63 करोड़
डीएम स्कूल बरखेड़ा पठनी से भेल सीवेज	3 किमी	5 करोड़
प्लांट व्हाया लहारपुर		
एक्स अस्पताल से डीआरएम ऑफिस	1 किमी	2 करोड़
सागर पब्लिक स्कूल साकेत नगर	1 किमी	3 करोड़
से 9 ए बीडीए कॉम्पलेक्स		
गैलेक्सी टॉवर से विक्रोय कॉलोनी	500 मीटर सीसी रोड	3 करोड़
भेल संगम, रजत विहार से दानिश नगर	1 किमी	3.87 करोड़
डोबरा से गांधी नगर	2 किमी	2 करोड़

कहां से कहां तक (ग्रामीण सड़कें)	लंबाई	खर्च होने वाली राशि
टीलाखेड़ी, देहरीकलां से झागरिया सरवर	10 किमी	10 करोड़
कुपना	1.20 किमी	2.40 करोड़
तारा सेवानिया, गुराड़िया, पृथ्वीपुरा, मन्नीखेड़ा, खेजड़ा देव	9 किमी	16 करोड़
गुनगा से गरोठिया	2 किमी	2.50 करोड़
खारपा गांव	500 मीटर	1 करोड़
अमझरा से पड़रिया जाट	3.20 किमी	4.50 करोड़ रुपए
बावड़ियाकलां रेलवे फाटक से बावड़िया गांव	डेढ़ किमी	3 करोड़
पिपलिया धाकड़ से फंदाखुर्द मार्ग पुल-बुलियाओं का मजबूतीकरण	----	1.5 करोड़
एनएच-356	35 किमी	70 करोड़
भोपाल बायपास से डोबरा, कोठार, धर्मा, नलखेड़ा, खजूरिया, रामदास बैरसिया मार्ग	44 किमी	----

नहीं हुए पिछले बजट के यह काम

पिछले बजट में शैतान सिंह तिराहे से कोलार मेन रोड को जोड़ने वाली सड़क और बावड़िया के प्रस्तावित आरओवी की एप्रोच रोड का काम होना था। एक साल में यह काम नहीं हो सके हैं।



सड़क-पुल निर्माण के जरिये किया जाएगा बेहतर संपर्क

बजट दस्तावेज के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क विकास कार्य किए जाएंगे। बजट में सड़कों और पुलों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। दस्तावेज के अनुसार ग्रामीण और शहरी संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही, पूंजीगत निवेश के अंतर्गत विभिन्न निगमों और मंडलों द्वारा 17,350 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश का भी उल्लेख है। सीएम मजरा टोला के तहत 20900 किमी सड़क बनाने का स्टेटस दिया गया है। सड़क रिपेयर के लिए 12,690 करोड़ का प्रावधान है।



8 वीं तक की छात्रों को टेट्रा पैक दूध



इस तरह आया बजट: उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को इसी लाल बैग को लेकर बजट भाषण के लिए विधानसभा में पहुंचे। यह पहली बार है जब मध्यप्रदेश में पेपलैस बजट प्रस्तुत किया गया।

देवड़ा ने बताया कि कक्षा 1 से 8 वीं तक के छात्रों को शासकीय संस्थानों में टेट्रा पैक (पोषण युक्त) दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यह यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के तहत मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना और पोषण स्तर में सुधार लाना है।

सिंहस्थ के लिए 13,851 करोड़: देवड़ा ने बताया कि सिंहस्थ के लिए 13हजार 851 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सिंहस्थ के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान 3 हजार 60 करोड़ के बजट रखा गया है। जिससे वहां अधोसंरचना, यातायात, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा। दो साल में मिले 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव: देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नवाचार के चलते प्रदेश को पिछले 2 सालों में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वर्तमान परिदृश्य पर नजर डालें तो 19300 एकड़ भूमि पर औद्योगिक संस्थान और आईटी पार्क स्वरूप ले रहे हैं। उद्यम क्रांति योजना के तहत 16,451 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

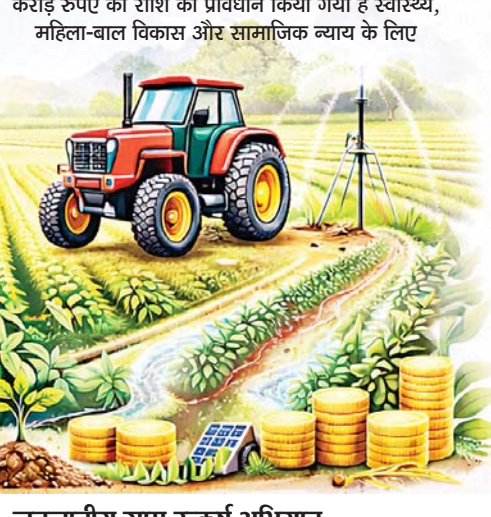
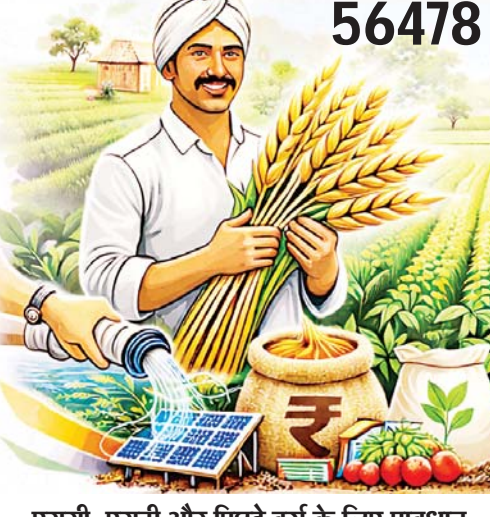
संबल योजना के लिए 950 करोड़ का प्रावधान : देवड़ा ने बताया कि सरकार ने बजट के माध्यम से आगे वित्तीय वर्ष के दौरान श्रम विभाग को 1 हजार 335 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत 950 करोड़ की राशि रखी गई है। **मेट्रो ट्रेन के लिए 656 करोड़ :** बजट में इंदौर और भोपाल के मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 656 करोड़ की राशि रखी गई है। देवड़ा ने कहा कि इस राशि का उपयोग कर मेट्रो परिसंचन के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। विशेष रूप से भोपाल की ऑरेंज और ब्लू लाइन के अलावा इंदौर मेट्रो के कार्यों को गति दी जाएगी।

गरीब कल्याण: सामाजिक सुरक्षा को आर्थिक नीति के केंद्र में रखा गया

सामाजिक क्षेत्र के लिए 56478 करोड़ आवंटित, पिछले साल से 15% अधिक

बजट 2026-27 में 'गरीब कल्याण' को सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि राज्य की आर्थिक नीति अब केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को भी समान महत्व दिया जा रहा है। सरकार ने सामाजिक क्षेत्र जिसमें स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं शामिल हैं, के लिए 56,478 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वर्ष के 48,928 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।

यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा मजबूत करना चाहती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2,857 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सहायता, विधवा पेंशन और अन्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सरकार ने स्वास्थ्य और पोषण को भी गरीब कल्याण से जोड़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, मातृ एवं शिशु देखभाल, पोषण कार्यक्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक गरीब वर्ग की पहुंच बढ़ाने की रणनीति स्पष्ट होती है। राज्य ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) आधारित बजटिंग को अपनाया है। यह दृष्टिकोण आय के आधार पर गरीबी को नहीं आंकता, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जैसे पहलुओं को भी शामिल करता है।



एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी अलग से बजट प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभागों के लिए कुल 24,024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है (पृष्ठ 35)। यह पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाता है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और बुजुर्ग समुदायों के लिए 1,691 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु 793 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसर बढ़ाना है। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 के 21,620 करोड़ रुपए की तुलना में 2026-27 में 29,663 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंचायत विभाग और नगरीय विकास के साथ मिलाकर कुल 61,665 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22363 करोड़ रुपए: स्वास्थ्य क्षेत्र को 13 फीसदी आवंटन



लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में 22,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 2025-26 के पुनरीक्षित अनुमान 21,731 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में संसाधन उपलब्ध होंगे। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि उपचार तक पहुंच में असमानता कम हो। आयुष विभाग के लिए 1,210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की नीति को दर्शाता है। इससे वैकल्पिक और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को गति मिलेगी। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के लिए भी 175 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में संसाधन उपलब्ध होंगे। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि उपचार तक पहुंच में असमानता कम हो। आयुष विभाग के लिए 1,210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों

क्या होता है रोलिंग और शून्य बजट

बजट में वित्त मंत्री ने रोलिंग बजट पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट रोलिंग आधारित है, यानी कि अगले 3 सालों के रोडमैप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिसमें यह तय होगा कि क्या काम कराए जाएंगे और उन्हें किस स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल रोलिंग बजट को सतत बजट के तौर पर देखा जाता है। एक निश्चित अवधि समाप्त होने पर अगले महीने या तिमाही स्वतः ही उसमें जुड़े जाता है, यानी कि निर्धारित समय के बाद अगले समय तक लिए राशि स्वीकृत मानी जाती है। इसी तरह जीरो बजट में बीते वर्ष के खर्चों को आधार नहीं मानते हुए प्रत्येक नए चक्र में बजट शून्य से तैयार किया जाता है। इसमें हर व्यय को क्यों और कैसे सिद्ध करना होता है।

228 बर्थ वेटिंग रूम होंगे स्थापित

देवड़ा ने कहा कि सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं पर भी है। स्वास्थ्य मानव की पूंजी है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश के उन राज्यों में अग्रणी है, जहां डिजिटल स्वास्थ्य की पहल की गई है। सरकार का विशेष ध्यान उच्च जोखिम वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य सहायता और पुनर्वास प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बजट के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी स्वास्थ्य को प्रमुख मद के रूप में दर्शाया गया है, जहां कुल व्यय का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित है। यह अनुपात बताता है कि बुनियादी ढांचे और कृषि के साथ-साथ मानव विकास को भी समान महत्व दिया जा रहा है।

प्रतिक्रिया बजट पर भोपाल के कारोबारी संगठनों की राय मिली-जुली

इकोनॉमी बढ़ेगी लेकिन व्यापारियों की आस रही अधूरी

मुख्य संवाददाता, भोपाल। प्रदेश सरकार के मंगलवार को आए बजट के बाद प्रदेश के कारोबारी जगत से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राज्य के इस बजट से व्यापारिक संगठनों को काफी आस थी, लेकिन इनमें से अधिकांश पूरी न हो सकी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बजट अधिभाषण में एक तरफ जहां प्रदेश के इफ्का सेक्टर के साथ महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली नई नीतियों की सौगात मिली वहीं राज्य के करों में कमी, लाइसेंस के नियमों में सरलीकरण एवं प्रदेश में ई कॉमर्स पॉलिसी को लेकर कई उम्मीदें थीं जो इस साल पूरी नहीं हो सकीं।

देश में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केिट) के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र शर्मा के अनुसार बजट में महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार, कृषि समर्थन तथा शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र में नए प्रावधान सराहनीय हैं, जो समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। कास तौर से महिलाओं के लिए योजनाएं, मेट्रो व सड़क परियोजनाओं और ग्रामीण विकास पर फोकस से प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इसके अलावा व्यापारियों को आस थी कि एमएसएमई और लघु व्यापारियों को कर राहत, लाइसेंस प्रक्रिया में सरलीकरण, स्थानीय व्यापार संरक्षण, ई ऑमर्स नीति और युवाओं के लिए उद्योग लगाने के लिए वेस प्रावधान की उम्मीदें थीं, जो पूरी नहीं हो पाई। शर्मा के मुताबिक विकास योजनाओं के साथ व्यापार और उद्योग को भी मजबूत करने की रणनीति जोड़ी जाती तो यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता था है।

नई व्यापार नीति लाएं वित्त मंत्री

प्रदेश सरकार के बजट के बाद भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने कहा कि इस बजट में कारोबारियों और उद्योगपतियों की आशाएं पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि व्यापारियों को आस थी कि भोपाल समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में उद्योग लगाने और नए कारोबार की स्थापना को लेकर विशेष रियायतों की घोषणा की जाएगी। गोयल के मुताबिक प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू व्यापारी और इंडस्ट्री से मिलता है, ऐसे में उनके लिए कोई घोषणा होती तो इसका आर्थिक फायदा भी राज्य सरकार को मिलता। उन्होंने मांग उठाई है कि बजट के बाद वित्त मंत्री व्यापारियों और उद्योगपतियों की सलाह के अनुसार ऐसी योजना बनाए जिससे भोपाल और अन्य शहरों में नए कारोबार आसानी से शुरू किए जा सकें।

शिक्षा कौशल, उद्योग रोजगार पर फोकस: चतुर्वेदी

सीआईआई मध्यप्रदेश के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा है कि राज्य सरकार के बजट को रोजगार, उद्योग और शिक्षा कौशल विकास पर संतुलित फोकस है 48 नए औद्योगिक पार्कों की घोषणा राज्य में विनिर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करेगी, जिससे स्थानीय रोजगार सृजन और एमएसएमई वृद्धि को बल मिलेगा। इसी तरह बजट में पूंजीगत व्यय को 1 लाख से अधिक रखने का निर्णय आधारभूत ढांचे तथा औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। शिक्षा और कौशल में वृद्धि पर भी बजट में जोर दिया गया है। चतुर्वेदी ने कहा कि उनका ऐसा मानना है कि यह बजट उद्योग, नवाचार एवं कुशल कार्यबल के विकास के लिए प्रोत्साहित देता है और राज्य को एक मजबूत आर्थिक तथा औद्योगिक केन्द्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगा।

7.95 लाख विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी बड़े स्तर पर बजट का प्रावधान किया गया है।

11,277 गांवों के लिए 793 करोड़

जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 11,277 गांवों के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। **कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़** सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुलभ स्टैडियम बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया है। लाइली लक्ष्मी योजना में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्गों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है।

भारत ने ग्रुप-ए के अंतिम मैच में नीदरलैंड को 17 रन से हराया, लगातार चौथा मैच जीता

दुबे की दहाड़, वरुण के चक्रव्यूह से टीम इंडिया का विश्व कप में विजयी रथ जारी



जेएनएन, अहमदाबाद

शिवम दुबे के तूफानी अर्धशतक के बाद वरुण चक्रवर्ती के फिरकी के जादू से भारत ने टी-20 विश्व कप के ग्रुप-ए मैच में बुधवार को नीदरलैंड को 17 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथा जीत दर्ज की। भारत ने टी-20 विश्व कप में लगातार 12वीं जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में भारत 2024 से ही अजेय बना हुआ है। भारत चार मैच में आठ अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहा, जबकि नीदरलैंड ने अपने अभियान का अंत चार मैच में एक जीत से दो अंक के साथ किया। भारत के 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम वरुण (14 रन पर तीन विकेट) और शिवम दुबे (35 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदों के सामने सात विकेट पर 176 रन ही बना सकी। नीदरलैंड की ओर से बास डि लीडे ने सर्वाधिक 33 रन बनाए। नोह क्रोस (12 गेंद में नाबाद 25 रन) तथा जैक लियोन कैशे (16 गेंद में 26 रन) ने सातवें विकेट के लिए 23 गेंद में 47 रन की साझेदारी की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। भारतीय टीम अपना अगला मैच इसी मैदान पर सुपर आठ चरण में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी।

अंतिम पांच ओवर में भारत ने जोड़े 75 रन

नीदरलैंड के ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त ने भारत के ऊपरी क्रम के तीन बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर बढ़त बनाई और अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए। उनके तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को रनों की रफ्तार को बढ़ाने नहीं दिया, 15 ओवर के बाद रन रेट को आठ से कम रखा, लेकिन शिवम की 66 रन की पारी ने गेंदबाजों को आरामदायक जीत के लिए पर्याप्त स्कोर दे दिया। प्लेयर ऑफ द मैच दुबे ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 66 रन की पारी खेलने के अलावा हार्दिक पंड्या (30) के साथ पांचवें विकेट के लिए 35 गेंद में 76 रन की साझेदारी की, जिससे भारत ने छह विकेट पर 193 रन बनाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव (34) और तिलक वर्मा (31) ने भी उपयोगी पारियां खेली। दुबे और हार्दिक 14वें ओवर में उस समय साथ आए जब भारत 110 रन पर चार विकेट गंवाकर संकट में था। इन दोनों की पारियों से भारत अंतिम पांच ओवर में 75 रन जोड़ने में सफल रहा।

■ नई गेंद से थोड़ी मदद मिल रही थी और नीदरलैंड के सलामी बल्लेबाजों का सामना अर्शदीप और बुमराह जैसे दो बेहतरीन गेंदबाजों से था। बदलाव के तौर पर दोनों ने लगातार चार ओवर तक गेंदबाजी की, हवा और सीम दोनों से गेंद को रिविंग कराया, 12 फाल्स शॉट निकलवाए और सिर्फ 22 रन दिए। रन रेट पीछे रहने के कारण नीदरलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, जिससे वरुण और हार्दिक को अपने पहले ही ओवर में विकेट का स्वाद चखने को मिल गया।

■ नौवें ओवर तक ही आवश्यक रन रेट 12 से ऊपर चला गया था, तब भारत ने अभिषेक और दुबे को गेंद थमाई, जिससे नीदरलैंड की पारी को थोड़ी रफ्तार मिली। हालांकि आखिरी आठ ओवरों में जब उन्हें 100 रन की जरूरत थी, तब भारत फिर वरुण के पास लौटा और उन्होंने लगभग हैट्रिक ले लिया। उन्होंने एकरमैन को स्ट्रॉंग पर आउट किया, जबकि दत्त को रॉन्बन गेंद पर बौलड किया। हैट्रिक गेंद पर वह एडवर्ड्स के डिफेंस को भेदने के लगभग करीब पहुंच गए थे, लेकिन चूक गए। दुबे ने अपने पहले नौ गेंदों में 23 रन दे दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वाइड लाइन का सही इस्तेमाल किया और 14वें ओवर के अंत में बास डी लीडे को फाइनल शॉट थर्ड पर कैच कराया।

स्कोर बोर्ड

भारत: 193/6 (20 ओवर)	रन	गेंद	4	6
अभिषेक शर्मा वो. आर्यन दत्त	0	3	0	0
इशान किशन वो. आर्यन दत्त	18	7	2	1
तिलक का. डर मर्व वो. वैन वीक	31	27	3	1
सूर्यकुमार का. गगनेंद वो. क्लीन	34	28	2	1
दुबे का.गगनेंद वो. वैन वीक	66	31	4	6
हार्दिक का. डर मर्व वो. वैन वीक	30	21	0	3
रिंकू सिंह नाबाद	6	3	0	1

नीदरलैंड: 176/7 (20 ओवर)

लेविट का. सुंदर वो. हार्दिक	रन	गेंद	4	6
ओड्डाउड वो. वरुण	24	23	4	0
डे लीड का. वरुण वो. शिवम	33	23	3	1
एकरमैन का. रिंकू वो. वरुण	23	15	2	2
आर्यन दत्त वो. वरुण	0	1	0	0
स्कॉट एडवर्ड्स वो. बुमराह	15	10	2	0
केच लायन का. सुंदर वो. शिवम	26	16	1	1
नोवा क्रोस नाबाद	25	12	5	0
लोजन वैन वीक नाबाद	4	2	1	0

■ अभिषेक शर्मा विश्व कप में लगातार तीसरे मैच में बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। उनकी पिछली सात पारियों की बात करें तो उन्होंने 0, 68*, 0, 30, 0, 0 और 0 रन बनाए हैं। यानी पिछली सात पारियों में अभिषेक के बल्ले से सिर्फ एक बार अर्धशतक निकल रहा है और कुल 98 रन ही बना सके हैं।

फरहान का शतक, नामीबिया पर सबसे बड़ी जीत के साथ पाकिस्तान सुपर 8 में तारिक की बेहतरीन गेंदबाजी, शादाब का ऑलराउंड प्रदर्शन

जेएनएन, कोलंबो

पाकिस्तान ने बुधवार को टी-20 विश्व कप के 'करो या मरो' के ग्रुप मैच में नामीबिया को 102 रन से हराकर सुपर आठ में प्रवेश किया। यह टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी है। सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की 11 चौके और चार छक्के जड़ित 58 गेंद में नाबाद 100 रन की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने तीन विकेट पर 199 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद पाकिस्तान ने 'मिस्ट्री' स्पिनर उस्मान तारिक (16 रन देकर चार विकेट) और लेग स्पिनर शादाब खान (19 रन देकर तीन विकेट) के स्पिन जाल से दबदबा बनाते हुए नामीबिया को 17.3 ओवर में महज 97 रन पर समेट दिया। सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज ने भी एक-एक विकेट झटका। नामीबिया के लारिन स्टीनकेप (23) और अलेक्जेंडर बुसिंग-वोल्शॉक (20) ने सर्वाधिक रन बनाए, जबकि अन्य बल्लेबाज दहाई का अंक भी नहीं छू सके।



■ 50 से 100 रन तक पहुंचने में फरहान को महज 20 गेंद लगीं। उन्होंने 58 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए, जो नामीबिया के पूरे स्कोर (97) से भी ज्यादा थे। फरहान विश्व कप में शतक जड़ने वाले पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 2014 में मीरपुर में अहमद शहाजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था।

बाँश के शानदार प्रदर्शन से यूएई को छह विकेट से हराया

सभी लीग मैच जीतकर दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर, यूएई ने हार के साथ ली विदाई

नई दिल्ली, जेएनएन। दक्षिण अफ्रीका ने टी-20 विश्व कप के अपने आखिरी ग्रुप लीग मैच में बुधवार को यूएई को छह विकेट से हराकर सुपर आठ की तैयारी पुख्ता कर ली। दक्षिण अफ्रीका उन टीमों में से है, जिन्होंने लीग स्टेज में एक भी मैच नहीं गंवाया। पिछली उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को सुपर 8 के पहले मैच में 22 फरवरी को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन और मेजबान भारतीय टीम से खेला नहीं। वहीं यूएई ने टूर्नामेंट से हार के साथ विदा ली। पहले गेंदबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच कॉर्विन बाँश के तीन विकेट की मदद से यूएई को छह विकेट पर 122 रन पर रोकने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 123 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने पावरप्ले में ही 56 रन बना लिए थे। हालांकि उनके दो विकेट भी गिरे। कप्तान ऐडन मार्क्रम (11 गेंदों में 22 रन) चौथे ओवर में वह हैदर अली



की गेंद पर बोल्लड हो गए। इसके बाद मोहम्मद जवाहुदुल्लाह ने विंक्टन डिकॉक (14) को कैच आउट करते हुए दूसरा झटका दिया। इसके बाद रायन रिक्लट्ट (30) और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच 49 रनों की तेज साझेदारी हुई, जिसने दक्षिण अफ्रीका को जीत के मुहाने पर खड़ा कर दिया।

सिटी स्पोर्ट्स

इंटर कॉलेज क्रिकेट: उत्कर्ष के ऑलराउंड प्रदर्शन से टूबा जीता



भोपाल, खेप। प्लेयर ऑफ द मैच उत्कर्ष पांडे के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत टूबा कॉलेज ने इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रेस्टीज कॉलेज को 87 रन से करारी शिकस्त देते हुए विजयी शुरुआत की। आईईएस यूनिवर्सिटी कैम्पस में टूबा कॉलेज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में चार विकेट खोकर 176 रन का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में प्रेस्टीज कॉलेज की टीम 89 रन पर ऑलआउट हो गई। उत्कर्ष ने 17 गेंदों में 51 रन बनाने के बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट भी झटके। इससे पहले टूर्नामेंट का शुभारंभ आईईएस यूनिवर्सिटी के सीईओ देवाश सिंह ने किया।

अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में हिस्सा लेंगे मध्यप्रदेश के उदित पटेल

भोपाल, खेप। मध्यप्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी के खिलाड़ी उदित पटेल का चयन भारतीय सीनियर रिसलिंग टीम में किया गया है। उदित ग्रीको रोमन शैली के 60 किलोग्राम भार वर्ग में मुहम्मद मालो अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लेंगे। यह टूर्नामेंट में 26 फरवरी से 02 मार्च तक अल्बानिया के तिराना में आयोजित किया जाएगा।

सिविल सर्विसेज क्रिकेट: मप्र ने हरियाणा को 33 रन से हराया



भोपाल, खेप। मध्यप्रदेश ने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज क्रिकेट टूर्नामेंट में हरियाणा को 33 रनों से शिकस्त दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मप्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 136 रन बनाए। कप्तान पीयूष नेवारे ने 60 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि अबुज खान ने 49 रन बनाए। जवाब में हरियाणा की टीम 103 रन पर ढेर हो गई। मप्र के लिए निलेश राहंगडाले ने 4 और विशाल कहार ने 2 विकेट झटके। विनीत एवं आदर्श को एक-एक सफलता मिली। निलेश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

महिला टीमों के बीच दूसरा टी-20 आज दोपहर 1:45 बजे से ऑस्ट्रेलिया पर अजेय बढ़त हासिल करने उतरेगा भारत

कैनबरा, जेएनएन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम गुरुवार को जब दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी, तो वह पहले मैच में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से प्रेरणा लेने की कोशिश करेगी। तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने पहले मैच में चार विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को झकझोर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई और केवल 133 रन पर आउट हो गई। भारतीय बल्लेबाजों को हालांकि बारिश के कारण खेलने का खास मौका नहीं मिला। भारत ने यह मैच डकवर्थ-अर्धशतक निकल रहा है और कुल 98 रन ही बना सके हैं।



■ इस साल इंग्लैंड में होने वाले महिला टी-20 विश्व कप को देखते हुए भारत के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीतने से भारत को आत्मविश्वास मिलेगा। ■ नई कप्तान सोफी मोलिनी की अगुआई वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम बदला लेने और सीरीज बराबर करने के लिए बेताब होगी। उसकी टीम में भले ही विश्व क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी वेथ मूनी, फोएबे लिटफील्ड, एलिसे पेरी और एशले गार्डनर शामिल हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर भारी दबाव होगा।

पैरालंपिक खेलों में रूसी ध्वज और राष्ट्रगान की वापसी

मिलान, जेएनएन। रूसी खिलाड़ी एक दशक से अधिक समय में पहली बार पैरालंपिक शीतकालीन खेलों में अपने देश के ध्वज के तले प्रतिस्पर्धा करेंगे और उसके किसी खिलाड़ी के स्वर्ण पदक जीतने पर पदक वितरण समारोह में रूस का राष्ट्रगान बजाया जाएगा। इसकी घोषणा मंगलवार को की गई, जिसका मतलब है कि लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से काफी पहले ओलंपिक जगत में रूस और उसकी राष्ट्रीय पहचान पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने बयान में कहा कि रूस की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति को आगामी मिलान कोर्टिन पैरालंपिक खेलों के लिए छह स्थान आवंटित किए गए हैं। यह 2014 में रूस के सोची में हुए पैरालंपिक शीतकालीन खेलों के बाद पहली बार होगा, जब पैरालंपिक खेलों में रूस का ध्वज फहराया जाएगा।

विजयी गोल दागने के बाद विनीसियस ने लगाए नस्लीय दुर्व्यवहार के आरोप

मैड्रिड, जेएनएन। ब्राजील के खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के प्लेऑफ के मुकाबले में रियल मैड्रिड की तरफ से बेनफिका के खिलाफ विजयी गोल करने के बाद नस्लीय दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। खेल के तब रोक दिया गया जब विनीसियस ने दावा किया कि रियल मैड्रिड की 1-0 से जीत के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी ने नस्लीय टिप्पणी करके उनका अपमान किया। इस बीच मौजूदा चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) को मोनाको के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पीएसजी एक समय दो गोल से पीछे चल रहा था, लेकिन स्थानापन्न खिलाड़ी डेजायर डूप के शानदार प्रदर्शन से वह आखिर में 3-2 से जीत हासिल करने में सफल रहा।



अन्य मैचों में गैलाटसराय ने युवेंटस को 5-2 से हराया, जबकि बोरुसिया डॉर्टमुंड ने अटलान्टा के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की। विनीसियस ने स्टैडियम ऑफ लाइट में बेनफिका के खिलाफ प्लेऑफ के पहले चरण में रिकॉर्ड 15 बार के चैंपियन रियल मैड्रिड को बढ़त दिलाते हुए ब्राजील फ्रॉन्टोइस लेटेक्सियर को नस्लवादी टिप्पणी की जानकारी दी। उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाड़ी जियानलुका प्रेस्टिगानी की ओर इशारा किया। बेनफिका के कोच जोस मोरिन्हो ने हालांकि कहा कि उनके खिलाड़ी ने नस्लीय टिप्पणी करने के आरोपों से इनकार किया है। मोरिन्हो ने कहा कि उन्होंने मुझे अलग-अलग बातें बताईं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। जहां भी विनीसियस खेला, वहां हमेशा कुछ न कुछ हुआ।

जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में दो बार के पूर्व चैंपियन पश्चिम बंगाल को छह विकेट से हराया

जेएनएन, कल्याणी (पश्चिम बंगाल) जम्मू कश्मीर ने बुधवार को सेमीफाइनल के चौथे दिन दो बार के पूर्व चैंपियन बंगाल को छह विकेट से करारी शिकस्त देकर अपने 67 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। बंगाल ने जम्मू कश्मीर के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा था। जम्मू कश्मीर ने 34.4 ओवर में चार विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर दिया। उसकी तरफ से वंशज शर्मा ने नाबाद 43 और अब्दुल समद ने नाबाद 30 रन बनाए। इससे पहले तेज गेंदबाज आकिब नबी ने मैच में नौ विकेट लेकर बंगाल की जीत की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आईपीएल स्टार समद ने 22 साल के वंशज को विजयी रन बनाने का मौका दिया और इस युवा बल्लेबाज ने मुकेश कुमार की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर जम्मू कश्मीर की टीम में जबरदस्त जश्न का माहौल बना दिया। जम्मू कश्मीर ने तीसरे के दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 43 रन बनाए थे। बंगाल ने पहली पारी में 328 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जम्मू कश्मीर ने 302 रन बनाए। बंगाल हालांकि पहली पारी की मामूली बढ़त का फायदा नहीं उठा पाया और उसकी टीम दूसरी पारी में केवल 99 रन पर आउट हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच नबी ने कहा कि हमने कड़ी मेहनत की और हम इसके हकदार थे।

जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में



■ जम्मू कश्मीर ने इस सत्र से पहले 334 रणजी मैच खेले थे, जिनमें से उसने केवल 45 जीते थे। उसे अपनी पहली जीत दर्ज करके में 44 साल लगे गए, जो उसने 1982-83 में सेना के खिलाफ हासिल की थी। उसके लिए नॉकआउट में पहुंचना कभी आसान नहीं रहा, लेकिन 2013-14 में उसे एक बड़ी सफलता मिली जब उसने नेट रन रेट के आधार पर गोवा को पीछे छोड़कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उसने 2015-16 में परवेज रज्जल की कप्तानी में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई को हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। ■ जम्मू कश्मीर ने पहली बार 1959-60 के सत्र में रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था और तब से लेकर अब तक उसे मजबूत दावेदार नहीं माना जाता था। अब टीम खिताब से एक कदम दूर है।

■ मुंबई के विलाफ शुरुआती हार के बाद जम्मू कश्मीर ने राजस्थान के खिलाफ पारी की जीत तथा दिल्ली और हैदराबाद के विलाफ महत्वपूर्ण जीत हासिल करके नॉकआउट में प्रवेश किया। उसने क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश को 56 रन से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

स्मरण के शतक से कर्नाटक को 802 रन की विशाल बढ़त

लखनऊ। रविचंद्रन स्मरण (127) के लगातार दूसरे शतक की मदद से कर्नाटक ने उत्तराखंड के खिलाफ दूसरी पारी में छह विकेट पर 299 रन बनाकर कुल बढ़त 802 रन तक पहुंचा दी। इतनी बड़ी बढ़त के साथ कर्नाटक ने जम्मू और कश्मीर के खिलाफ खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है। चौथे दिन के पहले सत्र में उत्तराखंड को पहली पारी में 233 रन पर आउट करके कर्नाटक ने 503 रन की बढ़त हासिल की। इतनी बड़ी बढ़त के बावजूद कर्नाटक ने फॉलोऑन नहीं दिया और 26 फरवरी से शुरू होने वाले फाइनल से पहले अपने बल्लेबाजों को और अभ्यास का मौका देने के लिए दूसरी पारी का इस्तेमाल किया। कर्नाटक ने कुथिक कृष्णा और श्रेयस गोपाल जैसे निचले क्रम के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी का मौका देने के लिए बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा। और कृष्णा ने 52 रन बनाकर इसका अच्छा इस्तेमाल किया।

पाक हॉकी टीम के कप्तान ने कहा-खेलने के लिए जाने से पहले हमें बर्तन धोने पड़े

महासंघ से हम अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते कराची, जेएनएन। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान शकील अहमद बट ने ऑस्ट्रेलिया के उथल-पुथल भरे दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रीय महासंघ की जमकर आलोचना की और कहा कि इस दौरे के दौरान उनकी टीम को न केवल होटल में बुकिंग नहीं होने के कारण सड़कों पर भटकना पड़ा, बल्कि मैच खेलने के लिए जाने से पहले बर्तन भी धोने पड़े। बट ने बुधवार को सुबह लाहौर पहुंचे अठ्ठार पत्रकारों से कहा कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) उनसे झूठ बोल रहा था और अब पानी सिर के ऊपर से बाहर चला गया है। बट ने कहा कि हम महासंघ के मौजूदा प्रबंधन के रहते हुए खेलना जारी नहीं रख सकते। जब खिलाड़ियों को मैच खेलने जाने से पहले रसोई साफ करनी पड़ती है और बर्तन धोने पड़ते हैं तो आप हमसे कैसे अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। सरकारी स्वामित्व वाले पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) ने यह पुष्टि की थी कि उसने ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय टीम के होटल में ठहरने की व्यवस्था के लिए पीएचएफ को एक करोड़ से अधिक पाकिस्तानी रुपए दिए थे। इसके बाद पीएचएफ को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान हॉकी टीम को कैनबरा जाने वाली अपनी अगली उड़ान से पहले सिडनी हवाई अड्डे पर 13-14 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बट ने कहा कि सबसे दुखद बात यह थी कि एयरबीएनबी ने केवल 10 दिन के लिए होटल बुक किया था, जबकि हमें 13 दिन तक रुकना था।

संक्षिप्त समाचार

सिब्ल का एपस्टीन से कोई संबंध नहीं: खेड़ा

नई दिल्ली, जेएनएन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्ल का नाम जेफ्री एपस्टीन फाइलिंग से जुड़े होने के दावों को खारिज किया है। भाजपा नेता इस मामले में झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा- जिस दस्तावेज का हवाला दिया जा रहा है, वह 59 पन्नों का एक कैलेंडर है, जिसमें न्यूयॉर्क में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों, कॉन्फ्रेंस और फंडरेजर की लिस्ट है। यह दस्तावेज कथित तौर पर 10 सितंबर 2010 को मार्गरेट्स रोजर्स ने एपस्टीन की निजी सहायक लेस्ली ग्रॉफ को भेजा था। सिब्ल को इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने वैश्विक शिक्षा सहयोग में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया था। खेड़ा ने स्पष्ट किया कि इस सम्मान समारोह का एपस्टीन से कोई संबंध नहीं था।

ममता ने आतंकित किया हटवा दिए सारे सबूत: ईडी

कोलकाता, जेएनएन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने जांच को प्रभावित करने के इरादे से सबूतों से छेड़छाड़ करवाई और अहम डिजिटल साक्ष्य नष्ट कराए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि एजेंसी को 'हथियार' की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसे 'आतंकित' किया गया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष दायर हलफनामे में ईडी ने आरोप लगाया कि, मुख्यमंत्री के निर्देश पर आईपीसी ऑफिस में कंप्यूटर डेटा के बैकअप की प्रक्रिया रोकवाई गई।

सीनियर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का निधन

मुंबई, जेएनएन। सीनियर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का मंगलवार को निधन हो गया। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस के परिवार ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। जिसके बाद मंगलवार दोपहर मुंबई के अंधेरी स्थित श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक्ट्रेस समय से कैंसर से जूझ रही थीं। 2019 में उन्हें मल्टीपल मायलोमा डायग्नोस हुआ था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान वे 17 दिन आइसोलेशन में रहीं। बता दें कि प्रवीणा देशपांडे ने सलमान खान की सुपरहिट फिल्म रेड्डी में शालिनी चौधरी का रोल प्ले किया था। इसके अलावा उन्होंने एक विनेट, गबबर इज बैक और परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण जैसी फिल्मों में काम किया।



चीन में बसंत उत्सव

ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, 50 यूएस फाइटर जेट किए रवाना

बातचीत सकारात्मक रही लेकिन अहम मुद्दों पर अब भी अहमति

वाशिंगटन डीसी, जेएनएन। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे हैं। इंडिपेंडेंट प्लाइट-टैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटरिंग ने कई एफ-22, एफ-35 और एफ-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिपोर्ट किया है। यह जानकारी अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को जिनवा में हुई दूसरी दौर की बातचीत के दौरान सामने आई है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते से जुड़े मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तय की गई शर्तों को ईरान मानने में पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान अमेरिकी मांगों नहीं मानता, तो अमेरिका का इस्तेमाल करेगा।

रिफ्यूजिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट भेजे

अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ कई एरियल रिफ्यूजिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट की ओर जाते देखे गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि विमान लंबे समय तक ऑपरेशन की तैयारी में हैं। इस बीच, अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से रवाना होकर मिड-अटलांटिक में पहुंच चुका है और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। अगले चार-पांच दिन में उसके पहुंचने की उम्मीद है।

अमेरिका के साथ बातचीत सकारात्मक रही: अरागची

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताया। दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बातचीत को लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि समझौते की दिशा में नई विड़की खुली है। बातचीत के बाद संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में अरागची ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि बातचीत से टिकाऊ और स्थायी समाधान निकलेगा, जो सभी संबंधित पक्षों और पूर्व क्षेत्र के हित में होगा।' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान किसी भी खतरे या हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि संकरे हिस्से में मिसाइल परीक्षण किए गए। ईरानी मीडिया ने सुरक्षा और समुद्री कारणों का हवाला देते हुए कहा कि यह बंदी कुछ घंटों के लिए रहेगी।

महाराष्ट्र: मुस्लिमों को 5% आरक्षण का आदेश रद्द 2014 में कांग्रेस अध्यादेश लाई थी, पास न होने से 10 साल से लटका था

मुंबई, जेएनएन। महाराष्ट्र सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक सरकारी रेजोल्यूशन (जीआर) जारी किया। इसके जरिए सरकार ने 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिमों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी और अर्धशासकीय नौकरियों में 5 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई थी। हालांकि, पिछले 10 सालों से यह आदेश इनवैलिड रहा है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया अध्यादेश तय समय (6 हफ्ते) में विधानसभा से पास नहीं करवाया जा सका, जिससे यह खुद ही इनवैलिड हो गया था। जुलाई 2014 में कांग्रेस-एनसीपी की गठबंधन की सरकार थी। अक्टूबर 2014 में सरकार बदल गई।

2008-2013: सरकार ने मुस्लिम समुदाय पर रिपोर्ट बनाई कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने से पहले पांच सालों (2008-2013) तक रिसर्च की। सरकार ने सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति पर कई कमेटीयोरिपोर्ट्स बनवाईं। नतीजा यह निकला कि मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्ग पिछड़े हैं, इसलिए आरक्षण की सिफारिश की गई।

जुलाई 2014: सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का आरक्षण देने का फैसला कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार में तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने मुस्लिमों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया। इसे अध्यादेश/सरकारी आदेश के जरिए लागू करने की कोशिश हुई। यह फैसला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया, इसलिए राजनीतिक विवाद भी हुआ। अगस्त से सितंबर के बीच नियम को लागू करने की शुरुआत हुई।

अक्टूबर 2014: फैसले को कोर्ट में चुनौती, हाईकोर्ट की रोक मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। बोम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण जारी रखने की अनुमति मिली। वहीं नौकरियों में 5 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि नौकरी वाले आरक्षण के लिए पर्याप्त डेटा नहीं दिखाया गया। 2015 से 2018 के बीच अदालतों में केस चलता रहा।

भारत के बाद अब यूएस की नजर जापान पर

वाशिंगटन, जेएनएन। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील के बाद अब जापान के साथ भी बड़ा व्यापार समझौता करने की घोषणा की है। इस समझौते के तहत जापान कुल 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें पहले चरण में 36 अरब डॉलर के तीन बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ट्रंप के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स से अमेरिका की इंडस्ट्री मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ के दबाव के कारण यह डील संभव हो पाई। पहले जापान पर ज्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन समझौते के बाद टैरिफ घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। डील में तीन मुख्य प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है। पहला तीनजेट टेक्सास में है, जहां लिफ्टफाइंडे नचुरल गैस यानी एलएनजी का एक बड़ा प्लांट बनेगा।

Advertisement for Bhopal Egg Rate 510/-, featuring 'वर्गीकृत' logo and 'Bhopal Egg Rate 510/-' text. It also mentions 'Rate Suggested by RS Agro P.I.P.L. and Associated Poultry farmers.' and 'सलाह' (Advice).

अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन के सोशल मीडिया पोस्ट पर खड़ा हुआ विवाद फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट की पोस्ट का दिया था जवाब

वाशिंगटन डीसी, जेएनएन। अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन के एक सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि अगर कुत्तों और मुसलमानों में से एक को चुनना पड़े तो यह मुश्किल फैसला नहीं है। दरअसल, रैंडी फाइन ने यह टिप्पणी न्यूयॉर्क में एक फिलिस्तीनी-अमेरिकी एक्टिविस्ट नरदीन किसवानी की पोस्ट के जवाब में की थी। किसवानी ने लिखा था कि कुत्ते अपवित्र हैं। ऐसे समय में जब न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है, कुत्तों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इन्हें बंद करना चाहिए। इस पर फाइन ने कहा कि दुनिया में 57 ऐसे देश हैं, जहां शरिया कानून लागू है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वहीं चले जाएं। अमेरिका 58वां मुस्लिम देश नहीं बनेगा। बाद में किसवानी ने कहा कि वह बस मजाक कर रही थीं। यह न्यूयॉर्क में सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की गंदगी को लेकर चल रही बहस से जुड़ा था। ऐसा उन लोगों के लिए कहा गया था, जो राजनीति में मुस्लिमों के बढ़ते प्रभाव को खतरा मानते हैं।



मुसलमानों को अमानवीय दिखाने का आरोप

किसवानी ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपने फार्म पर एक कुत्ते को गोली मारने की बात कही थी। किसवानी ने लिखा, 'क्रिस्टी नोएम ने अपने ही कुत्ते को गोली मारने की बात कही और ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम कह दे कि शहर पालतू जानवरों के लिए सही जगह नहीं है तो उसे मौत की धमकियां मिलने लगती हैं।' किसवानी ने फाइन पर फिलिस्तीनियों और मुसलमानों को अमानवीय दिखाने का आरोप लगाया।

'जंजीर' से 'शोले' तक : सलीम खान की कलम से पटकथा बनी सिनेमा की धड़कन

हिंदी सिनेमा में परदे के सामने खड़े सितारों पर ही रोशनी पड़ती है, लेकिन परदे के पीछे बैठा वो लेखक, जो किरदारों में जान डालता है कई बार गुमनामी की जिंदगी जीता है। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास रच देते हैं। जब बात हिंदी सिनेमा की हो, तो अभिनेताओं के नाम हर किसी के होंटों पर होते हैं, जैसे

अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, राजेश खन्ना, सलमान खान, पर कई बार वह इंसान सबसे ज्यादा अहम होता है जिसने उन्हें कहानी दी, किरदार दिए, पहचान दी। ऐसा ही नाम है सलीम खान का, जिनकी कलम ने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों की दुनिया को बदल दिया।



कार्यालय ग्राम पंचायत तूमड़ा जनपद पंचायत फंडा भोपाल

Table with 4 columns: क्र., प्रवर्ग आरक्षण, जनसंख्या, कुल दुकान आरक्षित. It lists various categories of shops and their numbers.

Table with 4 columns: क्र., प्रवर्ग आरक्षण, जनसंख्या, कुल दुकान आरक्षित. It lists various categories of shops and their numbers.

Table with 4 columns: क्र., प्रवर्ग आरक्षण, जनसंख्या, कुल दुकान आरक्षित. It lists various categories of shops and their numbers.

संपत्ति के अंतरण हेतु म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 65 एवं म.प्र. (पंचायत स्वयं संचालित का अंतरण) नियम 1994 का पालन किया जाएगा। नौलामी की प्रक्रिया Open Bid को कि Highest निकले वहां से प्रारंभ करके फिर खुली नौलामी के अनुसार की जावेगी। स्थावर संपत्ति का अंतरण लोक नौलामी द्वारा किया जावेगा अन्यथा नहीं। स्थावर संपत्ति दुकानें जिनकी लोक नौलामी द्वारा अंतरण किया जाना है, उसमें आरक्षण का पालन किया जाएगा। आर्क्षित श्रेणी के बोलोदार को अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इच्छुक बोलोदार दुकान क्रमांक के साथ दुकान के मूल्य की राशि का 05 प्रतिशत राशि जमा कर बोलो में भाग ले सकता है। उच्चतम बोलो स्वीकार किए जाने पर 18 दुकानों की नौलामी में बोलोदार को 25 प्रतिशत राशि नौलामी दिनांक से 07 दिवस में जमा करना होगा। उच्चतम बोलो स्वीकार किए जाने पर 11 दुकानों की नौलामी में बोलोदार को 25 प्रतिशत राशि नौलामी दिनांक से 07 दिवस में जमा करना होगा। उच्चतम बोलोदार द्वारा नियत समय सीमा में राशि जमा नहीं किए जाने पर जमा निशेध राशि (शर्त क्रमांक 6 एवं 7 की राशि जमा) संपाद हो जावेगी। जो की वापस नहीं की जा सकेगी। अस्वास्थ्य बोलोदार की जमा 05 प्रतिशत निशेध राशि वापस कर दी जावेगी। स्थावर संपत्ति का क्षेत्रफल 18 दुकानों हेतु 10*20 वर्गफीट एवं बरामदा 10*6 वर्गफीट एवं 11 दुकानों में से दुकान क्र. 1 से 8 तक 10*15 वर्गफीट एवं दुकान क्र. 9 से 11 तक 10*10 वर्गफीट एवं बरामदा 10*5 वर्गफीट रहेगा। पट्टा आवंटन लोक नौलामी द्वारा अंतरण किया जावेगी अंतरण प्राधिकारी को अनुमति है 10 वर्ष के लिए उच्चतम बोलोदार को आवंटित किया जावेगा। स्थावर संपत्ति का प्रत्येक पट्टा इस शर्त के अधीन होगा कि पट्टे की अवधि के दौरान देय वार्षिक भाड़ा अंतरण देय होगा। उक्त दुकानों का वार्षिक भाड़ा 1200/- रुपये प्रतिवर्ष (रु 100 प्रतिवर्ष) रहेगा। उक्त 11 दुकानों का ऑफसेट मूल्य 5.00 लाख रहेगा एवं 18 दुकानों में से दुकान क्र. 1 से 13 तक की दुकान का ऑफसेट मूल्य 7.00 लाख एवं दुकान क्र. 14 से 18 तक का ऑफसेट मूल्य 06.00 लाख रहेगा। आरक्षण प्रवर्ग की दुकाने न तो अंतरित की जाएंगी और न ही किराए पर दी जाएंगी। शर्त उल्लंघन की दशा में आवंटन रद्द कर दिया जावेगा।

सरपंच सचिव ग्राम पंचायत तूमड़ा जनपद पंचायत फंडा भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत तूमड़ा जनपद पंचायत फंडा भोपाल

Table with 4 columns: क्र., प्रवर्ग आरक्षण, जनसंख्या, कुल दुकान आरक्षित. It lists various categories of shops and their numbers.

Table with 4 columns: क्र., प्रवर्ग आरक्षण, जनसंख्या, कुल दुकान आरक्षित. It lists various categories of shops and their numbers.

Table with 4 columns: क्र., प्रवर्ग आरक्षण, जनसंख्या, कुल दुकान आरक्षित. It lists various categories of shops and their numbers.

Advertisement for SBI (State Bank of India) featuring 'भारतीय स्टेट बैंक, गृह ऋण केंद्र' and 'कच्चा सूचना (अवल संपत्ति)'. It includes details about property auction and contact information.

जागरण, बुरखनपुर। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान एक छात्रा डोईफोड़िया परीक्षा केंद्र पर बेहोश हो गई, उसे तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बुरखनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। घटना बुधवार सुबह 12वीं कक्षा के रसायन शास्त्र के पेपर के दौरान हुई। ग्राम सावली की कनिष्ठा सिंग, डोईफोड़िया के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चल रही परीक्षा दे रही थी।

जागरण, अशोकनगर। जिले के प्रसिद्ध मां जानकी करीला मंदिर परिसर में रंगपंचमी मेले को लेकर बुधवार को मॉक ड्रिल किया गया। मुंगवाली एसडीएम इसार खान के निदेश पर एसडीआरएफ और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम ने ट्रस्ट के वॉलेंटियर्स और पुलिसकर्मीओं को आग पर काबू पाने के तरीके सिखाए। इसका उद्देश्य आगामी मेलों और भीड़ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखना है।



पेट सफा Laxative Green Tea

fssai
FSSAI NO. : 10924999000065

पेट सफा...
तो हर रोग दफा



Buy Now: amazon | Flipkart | blinkit | iim | bigbasket | snapdeal | JioMart

Sirf Ek कप चाय,
कब्ज को Tata Bye-Bye

Contact For Dealership 85588 07777 • dealership@divisa.in

“द्वीट ऑफ द डे”



अनुराग कश्यप फिल्म निर्देशक

मैं 2009 से मैक्सिमम सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। नेटफिलक्स ने इसे हरी झंडी दे दी थी। मैंने उनसे कहा, कृपया किताब पढ़ें। टीम में सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर किसी ने भी किताब नहीं पढ़ी थी। डेढ़ साल तक चुप्पी छाई रही, और किसी ने आकर मुझे यह नहीं बताया कि यह प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। वह खामोशी और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी।

संक्षिप्त खबरें

अवंतिका एक्स. के रिजर्वेशन कोच में घुसे अनाधिकृत यात्री

जागरण, इंदौर। इंदौर-मुंबई के बीच चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस पर रिजर्वेशन कोचों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को लेकर आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों की नाराजगी सामने आई है। यात्रियों ने बताया कि कोच एस-2 सहित अन्य स्लीपर डिब्बों में भीड़ इतनी अधिक थी कि आरक्षित सीटों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। एक यात्री ने शिकायत में लिखा कि उसकी मां, पत्नी और तीन वर्षीय बच्ची अवंतिका एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थीं, लेकिन कोच में अनाधिकृत यात्रियों की भीड़ के कारण सुरक्षा को लेकर चिंता की स्थिति बन गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ट्रेन में भीड़ नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ या रेलवे स्टाफ नजर नहीं आया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। यात्रियों ने इसे सुरक्षा की गंभीर चूक बताया। पूरी घटना को लेकर यात्रियों ने डीआरएम रतलाम, रेलवे सेवा से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक को टैग करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की।

एनएच-45 पर टक्कर से काले हिरण की गई जान



जागरण, नरसिंहपुर। जिले के नेशनल हाईवे-45 (भोपाल रोड) पर बुधवार को एक हदयविदारक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन को चपेट में आने से एक मादा काले हिरण की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब हिरण सड़क पार कर रहा था और तभी एक अनियंत्रित वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की तत्काल सूचना एक जागरूक राहगीर ने वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। हालांकि, प्रारंभिक जांच में टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान नहीं हो सकी है, जिसकी तलाश वन अमले द्वारा सरगमी से की जा रही है।

पटवारी ने जिंदा आदिवासी का काट दिया वारिस प्रमाण पत्र

बिचौलियों ने 2.50 करोड़ में जमीन सीमेंट कंपनी को बेची

मुख्य संवाददाता, भोपाल। मैहर जिले में एक जीवित आदिवासी का वारिस प्रमाण पत्र (वारिसाना) बनाकर उसकी बेशकमीती जमीन बिचौलियों ने छद्म करोड़ रुपए में सीमेंट कंपनी को बेच दी। जबकि नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद ही वारिसाना तैयार कर उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को दी जा सकती है। जिले के ग्राम भदनपुर में जीवित आदिवासी किसान को कागजों में मृत बताकर उसकी साढ़े तीन हेक्टेयर बेशकमीती जमीन को बिचौलियों और पटवारी ने मिलीभगत कर हड़प लिया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए तत्कालीन पटवारी सहित 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

इंदौर बेंच में ही सुना जाएगा भोजशाला विवाद का मामला

जागरण, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने साफ किया है कि बहुचर्चित भोजशाला, धार के विवाद का मामला इंदौर बेंच में ही सुना जाएगा। लिहाजा, हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि अगिलंब मामले से जुड़ा संपूर्ण रिकार्ड इंदौर भेजे। मामले की अगली सुनवाई इंदौर बेंच 23 फरवरी को होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एएसआई की सीलबंद रिपोर्ट की कापी सभी पक्षों को देने के बिंदु पर भी इंदौर बेंच ही निर्णय लेगी। राज्य की ओर से महाविधवा प्रशांत सिंह सहित अन्य वकीलों ने मामला मुख्यपीठ जबलपुर में ही सुने जाने पर बल दिया। इस पर सीजे सचदेवा ने साफ किया कि क्षेत्राधिकार की दृष्टि से यह मामला इंदौर बेंच में ही सुनवाई योग्य है।

जेपी अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में आग, फेल हुई फायर सेपटी

जागरण संवाददाता, भोपाल। राजधानी के जय प्रकाश (जेपी) अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में बुधवार दोपहर करीब 12.15 बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना प्रथम तल पर स्थित एक कमरे में हुई, जिसका उपयोग वर्तमान में सर्जिकल सामान और सैपल कलेक्टिंग उपकरणों के स्टोर के रूप में किया जा रहा था। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई, सुरक्षा उपकरणों की विफलता ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण माना जा रहा है। अस्पताल की पुरानी वायरिंग और संवेदनशील सामग्री के पास बिजली के खुले पॉइंट को लेकर पहले भी आशंकाएं जताई गई थीं। आग लगने के बाद ओपीडी ब्लॉक को खाली करा लिया गया और एहतियात के तौर पर बिजली काट दी गई। 45 मिनट तक अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल रहा। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर सवा बारह बजे स्टोर रूम से धुआं निकलता देख गाई हरिदेव यादव ने मोर्चा संभाला।



इसे हड़पने की साजिश रची। रामसिंह गौड़ जब जीवित थे उसी समय पटवारी ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उनके पुत्र राजेन्द्र सिंह के नाम पर वारिसाना दर्ज कर दिया। इसके साथ ही असली मालिक को अंधेरे में रखकर राजेन्द्र सिंह के नाम से फर्जी ऋण पुस्तिका भी तैयार कर ली गई। इसके बाद आदिवासी परिवार को बिचौलियों ने बैंक से लोन दिलाने का लालच दिया। इसी बहाने राजेन्द्र सिंह को इस खेल की शुरुआत साल 2012-13 के राजस्व रिकार्ड से हुई। भदनपुर निवासी रामसिंह गौड़ के पास लगभग 3.5 हेक्टेयर जमीन थी। तत्कालीन हल्का पटवारी अशोक सिंह ने बिचौलियों के साथ मिलकर

जांच में कसा शिकंजा, 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

ईओडब्ल्यू ने 13 साल तक लंबी जांच के बाद तमाम सबूत जुटाए तो पाया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन पटवारी अशोक सिंह, बिचौलिया शोभा प्रसाद कोल और बैजनाथ कोल, दीपक लालवानी, गोपाली उर्फ गोपाल आसवानी, अच्यु उर्फ अजय सावलानी, कमला उर्फ प्रदीप कुमार सेन एवं रामप्रकाश जायसवाल के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। इन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत धोखाधड़ी, दस्तावेजों में कट्टरचना, साजिश, की एफआईआर दर्ज कर ली है। अब ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई से जिले के राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसी अब इस घोटाले में शामिल अन्य राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत की भी पड़ताल कर रही है।

भारतीय छात्र रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर बेहद सजग: टोओईएफएल प्रमुख

नई दिल्ली, जेएनएन। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के वीजा नियमों में बदलाव, ऑपेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की स्थिरता पर सवाल और मिले-जुले राजनीतिक संकेतों ने छात्रों के बीच असहजता का माहौल बनाया है। कई छात्रों के लिए अब वैल्यू-फॉर-मनी का समीकरण दोबारा परखा जा रहा है। हाल में टैरिफ में कमी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अमेरिकी सरकार भारतीय छात्रों का भरोसा पूरी तरह बहाल कर पाएगी या नहीं, यह अब भी सवाल बना हुआ है। अमेरिकी विश्वविद्यालय ट्रूप प्रशासन द्वारा वीजा नियमों को कड़ा किए जाने से संतुष्ट नहीं हैं। प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़ी एजेंसियां भी दबाव महसूस कर रही हैं।



इसी बीच, टोओईएफएल और ग्री के ग्लोबल जनरल मैनेजर उमर चिहाने हाल ही में नई दिल्ली में थे। टोओईएफएल विवि प्रवेश, अकादमिक और वीजा उद्देश्यों के लिए एक मानकीकृत अंग्रेजी दक्षता परीक्षा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा के दौरान कोई विशेष घोषणा नहीं की जा रही है, बल्कि यह रेखांकित से एक है। हालिया घटनाक्रम पर उन्होंने कहा, भारतीय छात्र रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर बेहद सजग होते हैं। जब कोई एक गंतव्य अनिश्चित होता है, तो वे स्वाभाविक रूप से अन्य विकल्पों की तलाश करते हैं।

विकास की राह में पर्यावरण की अनदेखी नहीं: सीएम मुंबई के क्लाइमेट वीक-2026 में शामिल हुए सीएम

विशेष संवाददाता, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यदि हमें क्लाइमेट चेंज से भविष्य में आने वाली गंभीर चुनौती से बचना है, तो हमें आज से ही ठोस और समयबद्ध समाधान पर काम करना की जरूरत है। सतत् विकास की राह में हम पर्यावरण को अनदेखी नहीं कर सकते (उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश क्लाइमेट चेंज से निपटने में सर्वाधिक नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादक बन लौडन की भूमिका में है। डॉ. यादव बुधवार को मुंबई में क्लाइमेट वीक-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक गंभीर वैश्विक चुनौती है। क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व, आर्थिक स्थिरता और भावी पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना ही प्रगति का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि भारत की क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रतिबद्धताओं में भी राज्यों का योगदान भी महत्वपूर्ण है।

मध्यप्रदेश देश के सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में अग्रणी है। यहां लगभग हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। सीएम ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मग्न में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने का विश्वास और सुरक्षा की गारंटी देते हुए कहा कि राज्य और निवेशक मिलकर देश को नवकरणीय ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने की दिशा में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेशकों के साथ हमारा रिश्ता नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार-व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एनवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग (मप्र नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग) के अध्यक्ष एवं सीएम के लिए विख्यात सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन के बीच मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा

भांजे की शादी में मामा को आया हार्ट अटैक, मौत

जागरण, खरगोन। भांजे की शादी को लेकर चल रही मेहंदी की रस्म के दौरान दूरूहे के मामा को हार्ट अटैक आ गया। वे अपनी पत्नी के साथ नाचते-नाचते जमीन पर गिर पड़े। परिजनों ने इसे भी उनका डॉस स्टैप ही समझा। लेकिन कुछ देर तक जब वे नहीं उठे तो रिश्तेदार उनकी तरफ बढ़े, उन्हें निहाल देखकर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। मामला खरगोन के वझरा गांव का है। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बड़वानी में पिपलदु गांव के रहने वाले घनश्याम यादव भांजे की शादी में वझरा गांव आये थे। मंगलवार रात को मेहंदी की रस्म थी। इस दौरान घनश्याम अपनी पत्नी के साथ नाच रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य भी जश्न में शामिल थे। घनश्याम यादव पेशे से किसान थे और उनकी करीब आठ एकड़ जमीन है, उनके साथ पत्नी और बेटा भोला यादव भी मौजूद थे।

लोकायुक्त ने पटवारी और एसडीओ के रीडर को दबोच

मुख्य संवाददाता, भोपाल। बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने मंदसौर और मंडला जिलों में दो अलग-अलग ट्रैप में रिश्तखोर सरकारी कर्मचारियों का रिंगे हाथों दबोचा है। पहले मामले में उच्च निकाय को टीम ने मंदसौर जिले की सुवासरा तहसील में पदस्थ पटवारी हरीश पाटीदार को 30 हजार रुपये की रिश्त लेते हुए गिरफ्तार किया। पटवारी ने आवेदक दिनेश चंद्र जोशी से उनके दिवंगत भाई की कृषि भूमि का नामांतरण दत्तक पुत्र के नाम करने के एवज में कुल 40 हजार रुपये की मांग की थी, जिसमें से 10 हजार रुपये वह पहले ही ले चुका था। टीम ने पटवारी हरीश पाटीदार को तहसील कार्यालय में ही शेष रकम 30 हजार लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

Rajeev Gandhi Management Institute
Master of Business Administration (MBA)
Run by : Chouhan Education Society

Applications are invited for faculty positions in the area of Marketing, Finance and HR under Barkatullah University Code:28.

DIRECTOR-01	PROFESSOR -02
ASSOCIATE PROFESSOR -04	

The remuneration and qualification for all positions will be as per UGC / University Code 28 norms. Kindly apply with all testimonials and color photograph. Post or mail your resume before 25-FEB-2026 on director.rgmi@gmail.com

RGMI Campus, Salaiya Via. Danish Kunj, Kolar Road, Bhopal (M.P.)
Email : director.rgmi@gmail.com, Contact :9926995558, 9202528144

सरस्ती

मुख्यालयों व मलाईदार पदों पर सालों से जमे स्टाफ की होगी विदाई

मुख्य संवाददाता, भोपाल। मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल (एसएफ) की बटालियन और हेडक्वार्टर में सालों से एक ही कुर्सी पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का अब मैदानी (फील्ड) ड्यूटी का समय आ गया है। पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसएफ के एडीजी चंचल शेखर ने इसे लेकर प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया है। मंगलवार देर रात जारी इस आदेश के अनुसार अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बटालियन के मुख्यालय, कल्याण शाखा या अकाउंट्स जैसे महत्वपूर्ण पदों पर 3 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ नहीं रह पाएगा। हाल ही में मुरैना और जबलपुर में एसएफ की बटालियन में हुए करोड़ों के वित्तीय घोटालों को देखते हुए यह फरमान जारी किया गया है। आदेश में 5 बिंदु शामिल, नई व्यवस्था होगी लागू:



लिफ्ट हैं, उन्हें तत्काल हटाकर मैदानी (फील्ड) बटालियन में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही नई तैनाती के लिए भी कड़ी शर्तें तय की गई हैं। अब एमपी में एसएफ की 36 बटालियनों में से केवल उन चुनिंदा अफसरों और कर्मचारियों को ही मुख्यालय या ऑफिस की पोस्टिंग मिलेगी, जिन्होंने

कम से कम 3 साल तक लगातार बटालियन में एक्टिव और कठिन ड्यूटी की हो। आदेश में साफ कर दिया गया है कि एक बार तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद स्टाफ को दोबारा मुख्यालय की पोस्टिंग तभी मिलेगी, जब उसने कम से कम 3 साल फील्ड में गुजारे होंगे।

अर्दली और सुरक्षा ड्यूटी से होगी वापसी

एडीजी के आदेश के मुताबिक सुरक्षा या अर्दली ड्यूटी से बटालियन लौटने वाले स्टाफ को अब इसी तरह की नई ड्यूटी सौंपने के बजाय एक्टिव बटालियन में भेजा जाएगा, हालांकि हॉक फोर्स के जवानों को इससे छूट रहेगी। इन कर्मचारियों को अब किसी भी हाल में मुख्यालय में पदस्थ करने पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले एसएफ के कई कर्मचारी एक अफसर के यहाँ तैनाती खत्म होने पर दूसरे अफसर के यहाँ तैनाती करा लेते थे, जबकि अन्य कर्मचारी सालों तक फील्ड में ही पसीना बहाते रहते थे।

2022 से पहले वालों पर गिरेगी गाज

एडीजी ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि अब हर दो माह के अंतराल पर एसएफ रेंज के आईजी और डीआईजी इस आदेश के पालन की समीक्षा करेंगे और सीधे रिपोर्ट मुख्यालय भेजेंगे। आदेश में साफ है कि जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2022 के पहले से मुख्यालय या ऑफिस के पदों पर जमे हुए हैं, उन्हें तत्काल फील्ड ड्यूटी के लिए रवाना किया जाए।